नवसर्जन संस्कृति

PRGI No. GJHIN/25/A2786

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 01
अंक : 271
दि. 04.07.2026,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

52 हजार करोड़ रुपये के रक्षा आधुनिकीकरण को मिली मंजूरी: सेना, नौसेना और वायुसेना को मिलेंगे अत्याधुनिक हथियार, ड्रोन रोधी प्रणाली और उन्नत निगरानी तकनीक

नई दिल्ली। भारत की सैन्य शक्ति को और अधिक आधुनिक, आत्मनिर्भर तथा भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद (Defence Acquisition Council-DAC) की महत्वपूर्ण बैठक में लगभग 52 हजार करोड़ रुपये की लागत वाले रक्षा खरीद प्रस्तावों को आवश्यकता की स्वीकृति (Acceptance of Necessity-AoN) प्रदान कर दी गई। यह मंजूरी रक्षा खरीद प्रक्रिया का प्रारंभिक लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण चरण मानी जाती है, जिसके बाद विभिन्न हथियार प्रणालियों और सैन्य उपकरणों की विस्तृत खरीद प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

सरकार का उद्देश्य भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना की परिचालन क्षमता को आधुनिक तकनीकों से सशक्त बनाना, सीमाओं की सुरक्षा को और मजबूत करना तथा बदलते युद्ध परिदृश्य के अनुरूप तीनों सेनाओं को अत्याधुनिक संसाधनों से लैस करना है। हाल के वर्षों में ड्रोन युद्ध, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, साइबर खतरों और लंबी दूरी की निगरानी प्रणालियों के बढ़ते महत्व को देखते हुए इस पैकेज में पारंपरिक हथियारों के साथ-साथ नई पीढ़ी की रक्षा तकनीकों को भी विशेष प्राथमिकता दी गई है।

रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों में सबसे अधिक महत्व भारतीय सेना की युद्ध क्षमता को आधुनिक बनाने वाले उपकरणों को दिया गया है। सेना के लिए ड्रोन रोधी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली 'आकाश तरंग', कंधे से दागी जाने वाली टैंक रोधी निर्देशित मिसाइलें, मध्यम दूरी की भूमि से वायु में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, अति लघु दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, मुख्य युद्धक टैंकों के लिए सक्रिय सुरक्षा प्रणाली तथा जेट आधारित आत्मघाती ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। इन सभी प्रणालियों का उद्देश्य आधुनिक युद्धक्षेत्र में भारतीय सेना को अधिक प्रभावी, सुरक्षित और त्वरित प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाना है।

विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान समय में ड्रोन युद्ध सबसे बड़ी सैन्य चुनौतियों में से एक बनकर उभरा है। ऐसे में 'आकाश तरंग' जैसी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली अग्रिम मोर्चों पर तैनात सैनिकों को दुश्मन के ड्रोन हमलों से सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण

भूमिका निभाएगी। यह प्रणाली शत्रु के मानव रहित हवाई वाहनों की पहचान, निगरानी तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें निष्क्रिय करने में सक्षम होगी। सीमावर्ती क्षेत्रों में इसकी तैनाती से सेना की रक्षा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।

इसी प्रकार नई पीढ़ी की टैंक रोधी निर्देशित मिसाइलें पैदल सेना की मारक क्षमता को और मजबूत करेंगी। इन मिसाइलों के माध्यम से सैनिक दुश्मन के अत्याधुनिक टैंकों, बख्तरबंद वाहनों और मशीनीकृत सैन्य इकाइयों को अधिक प्रभावी ढंग से निशाना बना सकेंगे। आधुनिक युद्ध में तेजी से बदलती परिस्थितियों के बीच ऐसी मिसाइल प्रणालियां निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं।

रक्षा परिषद ने मध्यम दूरी की भूमि से वायु में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली को भी मंजूरी दी है। यह प्रणाली विभिन्न प्रकार के हवाई खतरों, जैसे लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के विरुद्ध प्रभावी सुरक्षा प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त अति लघु दूरी की वायु रक्षा प्रणाली को बहु-वर्णक्रमीय संवेदकों (मल्टी-स्पेक्ट्रल सेंसर) से लैस किया जाएगा, जिससे कम दूरी पर उत्पन्न होने वाले हवाई खतरों का तुरंत पता लगाकर उनका मुकाबला किया जा सकेगा।

टैंकों की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से सक्रिय सुरक्षा प्रणाली (Active Protection System) की खरीद को भी स्वीकृति दी गई है। यह प्रणाली दुश्मन द्वारा दागी गई एंटी-टैंक मिसाइलों और अन्य हमलों का समय रहते पता लगाकर उन्हें लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही निष्क्रिय करने में सक्षम होगी। इससे युद्धक्षेत्र में भारतीय टैंकों की सुरक्षा और जीवित रहने की क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी।

रक्षा पैकेज में शामिल जेट आधारित आत्मघाती ड्रोन प्रणाली भी सेना के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। ये उच्च गति वाले ड्रोन लंबी दूरी तक जाकर सटीक लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम होंगे। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता और आधुनिक नेविगेशन तकनीक से लैस ये ड्रोन भविष्य के युद्धों में भारतीय सेना को अधिक मारक और सटीक हमला करने की क्षमता प्रदान करेंगे।

भारतीय नौसेना के आधुनिकीकरण को भी इस रक्षा पैकेज में विशेष महत्व दिया गया है। परिषद ने नौसेना के लिए बहु-प्रभावी समुद्री बारूदी सुरंग (Multi-Influence Naval Mine), जहाज आधारित मानव रहित हवाई प्रणाली तथा विद्युत चालित प्रणोदन प्रणाली (Electric Propulsion System) के परीक्षण के लिए भूमि आधारित परीक्षण सुविधा (Land-Based Testing Facility) की स्थापना को मंजूरी दी है।

विशेषज्ञों के अनुसार समुद्री बारूदी सुरंगें समुद्री सुरक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। युद्ध की स्थिति में इनका उपयोग दुश्मन के युद्धपोतों और पनडुब्बियों की गतिविधियों को सीमित करने तथा रणनीतिक समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। वहीं जहाज आधारित मानव रहित हवाई प्रणाली (Ship-borne UAV) समुद्र में लंबी दूरी तक निगरानी, टोही अभियान और वास्तविक समय में सूचनाएं उपलब्ध कराने में नौसेना की क्षमता को कई गुना बढ़ाएगी। नौसेना के लिए स्वीकृत भूमि आधारित परीक्षण सुविधा भी अत्यंत महत्वपूर्ण आधारभूत परियोजना मानी जा रही है। इस सुविधा में भविष्य के युद्धपोतों में उपयोग होने वाली विद्युत चालित मोटरों और प्रणोदन प्रणालियों का परीक्षण किया जाएगा। इससे भारतीय नौसेना को अधिक आधुनिक, ऊर्जा दक्ष और तकनीकी रूप से उन्नत युद्धपोत विकसित करने में सहायता मिलेगी।

भारतीय वायुसेना को भी इस रक्षा पैकेज के अंतर्गत नई पीढ़ी की निगरानी प्रणाली उपलब्ध कराई जाएगी। परिषद ने उच्च ऊंचाई पर लंबे समय तक संचालित रहने वाले स्थिर पंखों वाले कृत्रिम उपग्रह मंच (High Altitude Pseudo Satellite Platform-HAPS) सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है। यह अत्याधुनिक प्रणाली पारंपरिक उपग्रह और ड्रोन के बीच की तकनीक मानी जाती है तथा लंबे समय तक ऊंचाई पर रहकर लगातार निगरानी करने में सक्षम होती है।

रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह प्लेटफॉर्म सीमावर्ती क्षेत्रों में खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी, संचार नेटवर्क को मजबूत करने, दूरस्थ संवेदन (Remote Sensing) तथा वास्तविक समय में सैन्य सूचनाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसकी सहायता से भारतीय वायुसेना को रणनीतिक निगरानी क्षमता में बड़ा लाभ मिलेगा और विभिन्न सैन्य अभियानों में अधिक सटीक निर्णय लेने में सहायता प्राप्त होगी।

रक्षा मंत्रालय का मानना है कि इन खरीद प्रस्तावों से केवल सैन्य शक्ति ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी रक्षा उत्पादन को भी गति मिलेगी। सरकार पिछले कुछ वर्षों से घरेलू रक्षा उद्योग, अनुसंधान संस्थानों और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर दे रही है, ताकि भारत रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम करते हुए वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर सके।

विशेषज्ञों के अनुसार आधुनिक युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। अब पारंपरिक हथियारों के साथ-साथ ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, साइबर सुरक्षा और नेटवर्क आधारित सैन्य प्रणालियां निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। ऐसे में रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा स्वीकृत यह लगभग 52 हजार करोड़ रुपये का रक्षा आधुनिकीकरण पैकेज भारतीय सशस्त्र बलों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे तीनों सेनाओं की संयुक्त युद्ध क्षमता, सीमाओं की सुरक्षा, त्वरित प्रतिक्रिया और रणनीतिक तैयारियों में उल्लेखनीय मजबूती आने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री विजय पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में पूर्व मंत्री अनीता आर. राधाकृष्णन गिरफ्तार, गिरफ्तारी पर सियासत तेज

चेन्नई। तमिलनाडु की राजनीति में शुक्रवार को उस समय नया विवाद खड़ा हो गया, जब मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के पूर्व मंत्री अनीता आर. राधाकृष्णन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के कुछ समय बाद की गई। गिरफ्तारी के बाद राज्य की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और विपक्ष ने सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अनीता आर. राधाकृष्णन को तूतीकोरिन जिले से लगभग 23 किलोमीटर दूर ऑथूर क्षेत्र के दौरे के दौरान हिरासत में लिया गया। बताया गया कि वह अपने विधानसभा क्षेत्र के कार्यक्रमों और निरीक्षण के सिलसिले में वहां पहुंचे थे। पुलिस टीम ने उन्हें मौके पर हिरासत में लेने के बाद औपचारिक गिरफ्तारी की प्रक्रिया पूरी की और पुलिस वाहन से अपने साथ ले गई। गिरफ्तारी

के दौरान क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। राधाकृष्णन की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही उनके समर्थक बड़ी संख्या में घटनास्थल पर पहुंच गए। समर्थकों ने पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए नारेबाजी की और आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष के नेताओं को निशाना बना रही है। कुछ समय तक वहां तनावपूर्ण स्थिति बनी रही, हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित रखते हुए गिरफ्तार नेता को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कार्रवाई पूरी की। इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक रूप ले लिया जब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने गिरफ्तारी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने सवाल उठाया कि जब राधाकृष्णन अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे, तब उन्हें तत्काल गिरफ्तार करने की ऐसी क्या आवश्यकता थी। स्टालिन ने आरोप लगाया कि राज्य की सत्तारूढ़ सरकार विपक्षी नेताओं के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने में अधिक रुचि दिखा रही है।

स्टालिन ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार को उन मामलों पर अधिक ध्यान देना चाहिए, जिनका संबंध महिलाओं की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से है। उन्होंने दावा किया कि एक महिला द्वारा सत्तारूढ़ दल के एक विधायक पर लगाए गए गंभीर आरोपों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जा रही, जबकि विपक्षी नेताओं के मामलों में प्रशासन तेजी से कदम उठा रहा है। उन्होंने सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की।

दूसरी ओर, पुलिस का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप की गई है। अधिकारियों के अनुसार, संबंधित मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद कानून के अनुसार गिरफ्तारी की गई। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि आगे की जांच और कानूनी प्रक्रिया अदालत के निर्देशों तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ाई जाएगी। गौरतलब है कि यह मामला मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है, जिस पर शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी। मामले की सुनवाई के दौरान राधाकृष्णन ने गिरफ्तारी से राहत पाने के लिए मद्रास हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तमिलनाडु में सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच पहले से चल रहा टकराव इस घटना के बाद और तेज हो सकता है। विपक्ष इस कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बता रहा है, जबकि सरकार और पुलिस का पक्ष है कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है और न्यायालय के आदेशों के अनुरूप ही कार्रवाई की गई है।

सोनम रघुवंशी को तत्काल राहत, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर फिलहाल रोक लगाने से किया इनकार; मेघालय सरकार की याचिका पर जारी किया नोटिस

नई दिल्ली। मेघालय में हनीमून के दौरान अपने पति की कथित हत्या के बहुचर्चित मामले में आरोपी सोनम रघुवंशी को फिलहाल राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उनकी जमानत पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मेघालय हाईकोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के आधार और गिरफ्तारी मेमो में हुई टाइपिंग त्रुटि को लेकर गंभीर सवाल उठते हैं। अदालत ने कहा कि चूंकि आरोपी महिला पहले ही जेल से रिहा हो चुकी है, इसलिए इस समय उसकी जमानत पर अंतरिम रोक लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता। साथ ही अदालत ने मेघालय सरकार की अपील पर सुनवाई स्वीकार करते हुए सोनम रघुवंशी को नोटिस जारी किया और उनसे जवाब मांगा कि उनकी जमानत क्यों न रद्द की जाए।

मामले की सुनवाई जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया केवल गिरफ्तारी मेमो में टाइपिंग की त्रुटि के आधार पर जमानत दिए जाने के निर्णय पर विचार किया जाना आवश्यक है। अदालत ने संकेत दिया कि हाईकोर्ट के आदेश के कानूनी आधार की विस्तृत समीक्षा की जाएगी, लेकिन फिलहाल आरोपी की रिहाई को देखते हुए तत्काल हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मेघालय सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर नोटिस जारी करते हुए सोनम रघुवंशी से अपना पक्ष रखने को कहा है। अदालत ने निर्देश दिया कि वह यह स्पष्ट करें कि किन परिस्थितियों में उनकी जमानत बरकरार रखी जानी चाहिए और उसे रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई में अदालत जमानत आदेश की वैधता और उससे जुड़े कानूनी पहलुओं पर विस्तार से विचार करेगी। सुनवाई के दौरान मेघालय सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाईकोर्ट के आदेश का कड़ा विरोध किया। उन्होंने पीठ के समक्ष दलील दी कि यह मामला अत्यंत गंभीर प्रकृति का है और उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए जमानत का आदेश उचित नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि राजा रघुवंशी की हत्या से जुड़े तथ्य इतने गंभीर हैं कि वे किसी भी व्यक्ति की अंतरात्मा को झकझोर सकते हैं। उनका तर्क था कि ऐसे मामलों में न्यायिक प्रक्रिया के प्रति अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए।

सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने हाल ही में सामने आए एक अन्य चर्चित आपराधिक मामले का भी उल्लेख किया, जिसमें 26 वर्षीय केतन अग्रवाल की कथित हत्या के आरोप में उनकी मंगेतर और उसके कथित सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने अदालत से कहा कि इस प्रकार के अपराधों की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और न्यायालय को ऐसे मामलों में विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। इस पर जस्टिस सुंदरेश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालत इस व्यापक मुद्दे पर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती और केवल वर्तमान मामले के तथ्यों तक ही सीमित रहेगी।

उल्लेखनीय है कि यह मामला उस समय राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया था जब मेघालय में हनीमून पर गए कारोबारी राजा रघुवंशी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने इसे हत्या का मामला मानते हुए उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी सहित अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की थी। बाद में मेघालय हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों में कथित त्रुटियों का हवाला देते हुए सोनम रघुवंशी को जमानत दे दी थी। इसी आदेश को चुनौती देते हुए मेघालय सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। इधर, मामले में मृतक राजा रघुवंशी के परिवार ने एक बार फिर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग दोहराई है। मृतक के भाई विपिन रघुवंशी ने शुक्रवार को कहा कि उनका परिवार लंबे समय से इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करता आ रहा है। उनका आरोप है कि एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अब तक मामले की स्वतंत्र केंद्रीय जांच के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। परिवार का कहना है कि यदि देश के अन्य चर्चित मामलों में परिस्थितियों को देखते हुए सीबीआई जांच का आदेश दिया जा सकता है, तो उनके भाई की हत्या के मामले में भी निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच सुनिश्चित की जानी चाहिए। उनका मानना है कि केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच किए जाने से पूरे मामले के सभी पहलुओं की निष्पक्ष पड़ताल हो सकेगी और परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ेगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी की जमानत पर तत्काल रोक लगाने से इनकार करते हुए मामले की सुनवाई जारी रखने का निर्णय लिया है। अब सभी की नजरें आगामी सुनवाई पर टिकी हैं, जिसमें शीर्ष अदालत यह तय करेगी कि मेघालय हाईकोर्ट द्वारा दिया गया जमानत आदेश कानूनी कसौटी पर कितना टिकता है और क्या उसे बरकरार रखा जाए या रद्द किया जाए।

21 जुलाई की 'शहीद दिवस' रैली पर हाई कोर्ट का सख्त रुख ममता और अभिषेक बनर्जी से चार सप्ताह में मांगा जवाब

कोलकाता। वर्ष 2018 में आयोजित तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की 21 जुलाई 'शहीद दिवस' रैली से जुड़े कथित अदालत अवमानना मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को निर्देश दिया है कि वे चार सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल कर अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों पर विस्तृत जवाब दें। याचिका में आरोप लगाया गया है कि टीएमसी की 21 जुलाई 2018 की रैली के दौरान हाई कोर्ट के उस पूर्व आदेश का पालन नहीं किया गया, जिसमें सार्वजनिक सभाओं के कारण मुख्य सड़कों को पूरी तरह अवरुद्ध न करने और आम नागरिकों तथा आपातकालीन सेवाओं के लिए पर्याप्त मार्ग खुला रखने के निर्देश दिए गए थे।

यह मामला एक अवमानना याचिका के माध्यम से अदालत के समक्ष पहुंचा है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि मई 2018 में हाई कोर्ट द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किए जाने के बावजूद जुलाई 2018 में आयोजित टीएमसी की विशाल रैली के दौरान कोलकाता की कई प्रमुख सड़कों पर यातायात गंभीर रूप से प्रभावित हुआ और अदालत के आदेशों की अनदेखी की गई। याचिका में कहा गया है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन के दौरान न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन सुनिश्चित करना आयोजकों की जिम्मेदारी थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

मामले की सुनवाई जस्टिस अरिजीत बनर्जी और जस्टिस अपूर्बा सिन्हा रे की डिवीजन बेंच ने की। अदालत ने निर्देश दिया कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी चार सप्ताह के भीतर अपना हलफनामा दाखिल करें और याचिका में लगाए गए सभी आरोपों पर अपना पक्ष स्पष्ट करें। इसके बाद याचिकाकर्ता को भी निर्देश दिया गया है कि वह टीएमसी नेताओं के जवाब मिलने के दो सप्ताह के भीतर अपना प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करे।

डिवीजन बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को निर्धारित की है। उस दिन अदालत दोनों पक्षों के हलफनामों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर मामले की आगे की सुनवाई करेगी।

याचिका में वर्ष 2018 के उस आदेश का उल्लेख किया गया है, जिसे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ज्योतिर्मय भट्टाचार्य और जस्टिस अरिजीत बनर्जी की डिवीजन बेंच ने पारित किया था। उस आदेश में स्पष्ट कहा गया था कि किसी भी सार्वजनिक सभा, राजनीतिक रैली या बड़े जमावड़े के कारण मुख्य सड़कों को पूरी तरह बंद नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि पैदल यात्रियों, एम्बुलेंस, दमकल वाहनों तथा अन्य आपातकालीन सेवाओं के निर्बाध आवागमन के लिए पर्याप्त रास्ता हर स्थिति में खुला रखा जाए।

याचिकाकर्ता का दावा है कि 21 जुलाई 2018 की रैली के दौरान इन निर्देशों का प्रभावी ढंग से पालन नहीं किया गया। इसके कारण शहर के कई हिस्सों में भारी यातायात जाम की स्थिति बनी, आम नागरिकों को घंटों तक परेशानी का सामना करना पड़ा और कार्यालय आने-जाने वाले लोगों सहित आवश्यक सेवाओं पर भी असर पड़ा। इसी आधार पर अदालत की अवमानना का आरोप लगाते हुए यह याचिका दायर की गई है।

गौरतलब है कि टीएमसी हर वर्ष 21 जुलाई को 'शहीद दिवस' के रूप में बड़े स्तर पर रैली आयोजित करती है, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक कोलकाता पहुंचते हैं। यह पार्टी का प्रमुख राजनीतिक कार्यक्रम माना जाता है, जिसके चलते शहर में व्यापक सुरक्षा और यातायात प्रबंधन की व्यवस्था करनी पड़ती है।

अब इस मामले में सभी की निगाहें 17 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई पर रहेंगी, जब अदालत ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी द्वारा दाखिल किए जाने वाले हलफनामों तथा याचिकाकर्ता के प्रत्युत्तर पर विचार करते हुए आगे की कानूनी प्रक्रिया तय करेगी।

संपादकीय

पहले हितधारकों की चिंताओं को दूर कीजिए

खाड़ी युद्ध के चलते उपजे ईंधन संकट ने भारत समेत पूरी दुनिया को सबक दिए हैं कि देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिये नये विकल्प तलाशे जाएं। भारत जैसे देश के लिये तो यह बड़ी चुनौती है क्योंकि हम पूरी तरह कच्चे तेल व गैस के लिये विदेशी संसाधनों पर ही निर्भर हैं। जिससे संकटपूर्ण स्थितियों में न केवल महंगाई बढ़ती है बल्कि हमारी दुर्लभ विदेशी मुद्रा भी दांव पर लगती है। ऐसे ही संकट से जूझने के लिये देश ने इथेनॉल के विकल्प पर गंभीरता से विचार किया। देश में पहले ही सामान्य पेट्रोल में बीस फीसदी इथेनॉल मिलाया जा रहा है। देश में विदेशी मुद्रा की बचत व आत्मनिर्भरता की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है। हाल ही में फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों के लिये ज्यादा इथेनॉल वाले ई-85 फ्यूल उपलब्ध कराया गया। लेकिन अभी भी उपभोक्ताओं और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के बीच कई मुद्दों को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। दरअसल,ये वाहन ई-85 यानी 85 फीसदी इथेनॉल और 15 फीसदी पेट्रोल तथा ई-100 यानी शुद्ध इथेनॉल वाले मिश्रण पर चलने के लिये डिजाइन किये गए हैं। जबकि पेट्रोल से चलने वाली सामान्य गाड़ियां ई-20 यानी बीस फीसदी इथेनॉल और 80 फीसदी पेट्रोल के अनुकूल होती हैं। दरअसल, चुनिंदा आउटलेट्स पर ई-85 उपलब्ध कराने का निर्णय आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने के मकसद से लिया गया है। यह एक हकीकत है कि आज भी देश का नब्बे फीसदी कच्चा तेल आयातित किया जा रहा है। दुनियाभर में गाहे-बगाहे पैदा होने वाले भू-राजनीतिक संकटों ने बार-बार देश के ऊर्जा इकोसिस्टम की खामियों को ही उजागर किया है। इसमें दो राय नहीं है कि फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों के लिये इथेनॉल को मुख्य ईंधन के रूप में बढ़ावा देने का मकसद ऊर्जा जरूरतों में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में बढ़ना है। वहीं दूसरी ओर इसके उपयोग से हम ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कमी ला सकते हैं।

निश्चय ही वाहनों में इथेनॉल को बढ़ावा देना देश में आयातित कच्चे तेल के दबाव को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। लेकिन इस बदलाव को सिरे चढ़ाने के लिए बहुत सोच-समझकर आगे बढ़ना चाहिए, जिससे लोगों की आशंकाएं दूर हो सकें। जरूरत लोगों का भरोसा हासिल करने की है। भारत में इथेनॉल मिले तेल के उपयोग ने इससे होने वाले तमाम फायदों को साबित किया है। इससे काफी विदेशी मुद्रा की बचत भी हुई है। साथ ही देश में इथेनॉल का सशक्त उद्योग विकसित हुआ है। यदि बाजार में इथेनॉल पर लोगों का भरोसा बढ़ता है और इसकी मांग बढ़ती है तो इससे किसानों को कमाई के नये अवसर मिल सकते हैं। इथेनॉल की ज्यादा मांग होने पर गन्ने और मक्का का बाजार विस्तार लेगा। वहीं दूसरी ओर ई-85 की कीमत पारंपरिक पेट्रोल के मुकाबले कम रखने के फैसले से, उन उपभोक्ताओं को फायदा हो सकता है, जिनके पास इसके अनुकूल गाड़ियां हैं। भले ही इस फ्यूल की ईंधन दक्षता कम हो, लेकिन यह कदम देश की अर्थव्यवस्था को संबल देगा। बहरहाल, इस उम्मीद के साथ ही, हमें हकीकत का भी ध्यान रखना है। दरअसल, ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनियों ने इंजन की क्षमता, जंग लगने, ईंधन सिस्टम पर प्रभाव और इसकी दीर्घकालिक क्षमता को लेकर चिंताएं जतायी हैं। निस्संदेह, इन मुद्दों को सीधे खारिज करने के बजाय इन पर गंभीर रूप से मंथन करना चाहिए। अगर इन मुद्दों का निराकरण नहीं होता है तो भ्रम व संशय की स्थिति बनी रहेगी। जिसे अविलंब दूर करने की भी जरूरत है। इस वैकल्पिक ईंधन की सहज उपलब्धता के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर व गाड़ियों को इसके अनुरूप बनाना, वैकल्पिक ईंधन की गुणवत्ता के मानकों का निर्धारण तथा इससे जुड़े तकनीकी प्रशिक्षण में सुधार किया जाना चाहिए। इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि बॉयोफ्यूल इतनी जल्दी फॉसिल फ्यूल का विकल्प नहीं बन सकता। इस बाबत पर्याप्त तैयारी, पारदर्शिता और सभी हितधारकों का सहयोग लेना जरूरी है। इस मामले में जल्दबाजी करने से बचा जाना चाहिए। यदि हम सजगता व सतर्कता से आगे बढ़ते हैं तो ई-85 एक सफल मॉडल बन सकता है। अन्यथा हम एक अच्छा मौका चूक सकते हैं।

दुनिया की छत से इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की तैयारी

> चीन का मानना है कि 'दुनिया की छत' तिब्बत से लॉन्च किए गए रॉकेट भारत के भीतर तक जा सकते हैं। चीनी एक्सपर्ट्स ने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटपुल्ट से लॉन्च किया गया रॉकेट पारम्परिक रॉकेट से अधिक स्थिर और अचूक होगा, साथ ही यह अपने भार को गति देने वाली मिसाइल से बहुत सस्ता भी होगा।

जो तिब्बत 'दुनिया की छत' के नाम से मशहूर था, अब चीन उसे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक मार्ग वाले रॉकेट लॉन्चिंग अधिकेंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है। पेइचिंग इंस्टिच्यूट ऑफ़ स्पेस साइंस के अंतरिक्ष विज्ञानी यू थांग ने पिछले हफ़्ते कहा, 'चीन की स्पेस इंडस्ट्री के कुछ बहुत ही साहसी और होनहार युवाओं ने दो दशक से भी ज़्यादा समय पहले शिंगहाई-तिब्बत पठार के ऊंचाई वाले और कम हवा वाले इलाकों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च ऑर्बिट बनाने का आइडिया दिया था। अब वो साकार हो रहा है।'

इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रॉकेट लॉन्च टेक्नोलॉजी, एक क्रांतिकारी अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रणाली है, जो पारंपरिक केमिकल, ईंधन के बजाय शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों (मैग्नेटिक फील्ड) का उपयोग करके रॉकेट या पेलोड को अंतरिक्ष में लॉन्च करती है। यह तकनीक लक्ष्य तक पहुंचने में सटीक है, और अंतरिक्ष यात्रा की लागत को काफी हद तक कम करने की क्षमता रखती है।

इस प्रणाली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रैक (विद्युत चुम्बकीय पटरियों) का उपयोग किया जाता है, जो विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा (कायनेटिक एनर्जी) में बदलती हैं। एक बार आवश्यक गति प्राप्त करने के बाद, पेलोड या छोटा रॉकेट वातावरण में ऊपर की ओर छूट जाता है, और अंतरिक्ष के लिए अपनी यात्रा जारी रखता है। इससे भारी मात्रा में ईंधन की बचत होती है। इसे ध्यान में रखें कि पारंपरिक रॉकेटों के कुल वजन का 80-90 प्रतिशत हिस्सा केवल ईंधन होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्चर इस ईंधन के भार को खत्म कर देते हैं, जिससे रॉकेट बहुत अधिक पेलोड (उपग्रह या उपकरण) ले जा सकते हैं। यह तकनीक अंतरिक्ष यान को पारंपरिक केमिकल इंजनों की तुलना में कहीं अधिक गति देती है। इससे मंगल ग्रह की यात्रा का समय 8-9 महीने से घटकर केवल 30-60 दिन होने का दावा किया जा रहा है। यह 300 किलोवाट तक की शक्ति पर काम करता है, और हाइड्रोजन के आवेशित कणों (प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन) को 100 किलोमीटर प्रति सेकंड की आश्चर्यजनक गति प्रदान करता है।

भारत में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक (विद्युत-चुंबकीय) रॉकेट लॉन्च तकनीक अभी भी शुरुआती अनुसंधान और विकास के चरण में है। भारत में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम (ईएमएएलएस) चीन से काफी पीछे है। चीन फ़ुज़ियान (टाइप 003) विमान वाहक पर अपने विद्युत चुम्बकीय कैटापुल्ट को सफलतापूर्वक चालू कर चुका है, अमेरिका के बाद ऐसा करने वाला वह दुनिया का दूसरा देश है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की ग्राउंड फोर्स रिसर्च इंस्टिट्यूट में तैनात प्रोफेसर हान ने इसे दुनिया में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट बताया, और कहा कि यह पूर्व निर्धारित योजना के मुताबिक बड़ी सफलताओं के साथ लगातार चल रहा है। हान ने '4,000 मीटर (13,123 फुट) से ज़्यादा ऊंचे पठार से सीधे डेटा इकट्ठा किया है। उन्होंने इस पर अनुसंधान किया है कि रॉकेट को ज़्यादा ऊंचाई वाले माहौल के लिए कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जाए, जहां सर्दियों में तापमान बहुत कम होता है, जिससे हवा का दबाव कम होता है। यह समुद्र तल के प्रेशर का लगभग आधा हो सकता है। इसका मतलब है उड़ान के दौरान हवा का घर्षण कम होता है, और शायद रेंज भी ज़्यादा होती है, खासकर तिब्बत जैसे दुनिया की छत पर रॉकेट को और भी ज़्यादा पावरफुल हथियार बना देगा।'

ज़ियांग चीन के पूर्वी सिचुआन प्रांत का शहर है। 2026 की शुरुआत में ज़ियांग में हाई-टेम्परेचर सुपरकंडक्टिंग नेविगेशन सिस्टम के सफल परीक्षण ने इस टेक्नोलॉजी को हकीकत के करीब ला दिया है। इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व 'ज़ियांग कमर्शियल एयरोस्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टिट्यूट' के शोधार्थी कर रहे हैं, जो चाइना एयरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉरपोरेशन की एक शाखा है। तकनीकी सफलताओं के बावजूद, अभी भी इंजीनियरिंग से जुड़ी बड़ी चुनौतियां बाकी हैं। ज़ियांग फ़ैसिलिटी चीन के पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च वेरिफिकेशन प्लेटफ़ॉर्म को सक्रिय रूप से चला रही है, जिसका महत्वाकांक्षी लक्ष्य 2028 तक 'इसरो' की तरह व्यावसायिक लांच वाले पैटर्न पर लाना है। अब सवाल है, क्या चीन इस तकनीक का सैन्य इस्तेमाल भी करने के प्रयास में है? चीन विद्युत-चुंबकीय तकनीक का इस्तेमाल मिसाइल और रॉकेट लॉन्चिंग के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में आक्रामक रूप से कर रहा है। पारंपरिक रासायनिक ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए, चीन इस तकनीक को जीरो-स्टेज बूस्टर के रूप में विकसित कर रहा है।

चीन की ज़ियांग कमर्शियल एयरोस्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टिट्यूट एक ऐसे सुपरकंडक्टिंग मैग्नेटिक लेविटेशन सिस्टम पर काम कर रही है, जो रॉकेट को जमीन से ही ट्रैक पर बिजली के जरिए सुपरसोनिक गति देने में सक्षम है। इससे रॉकेट के इंजन हवा में बहुत ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ही काम करेंगे, जिससे भारी लागत और ईंधन की बचत होगी। मिसाइल तकनीक के साथ चीन उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव (एचपीएम) और ईएमपी हथियारों का निर्माण कर रहा है। चीन ने अंतरिक्ष में मौजूद दुश्मन के सैटेलाइट्स या संचार प्रणालियों को बिना किसी विस्फोट के जाम या नष्ट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तकनीक का उपयोग कर रहा है। चीन, अपने फूचियान जैसे अत्याधुनिक विमान वाहक पोतों पर युद्धक विमानों को लॉन्च करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम को आगे बढ़ा रहा है। चीनी मीडिया का दावा है कि यह दुनिया का पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सरफेस-टू-सरफेस रॉकेट होगा। तिब्बत में इनका टेस्ट क्यों किया जा रहा है? इस बारे में चीन का मानना है कि 'दुनिया की छत' तिब्बत से लॉन्च किए गए रॉकेट भारत के भीतर तक जा सकते हैं। चीनी एक्सपर्ट्स ने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट से लॉन्च किया गया रॉकेट पारम्परिक रॉकेट से अधिक स्थिर और अचूक होगा, साथ ही यह अपने भार को गति देने (प्रोपल्शन सिस्टम) वाली मिसाइल से बहुत सस्ता भी होगा।

मगर सवाल है, क्या हमारी सीमाएं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक संचालित रॉकेट प्रणाली से सुरक्षित रहेंगी? चीन के साथ भारत की 4,056 किलोमीटर लंबी सीमा को दशकों से नजरअंदाज किया गया है। समय-समय पर भारतीय अधिकारी इसे अभेद बनाने की आवश्यकता पर बल देते हैं। सत्ता में आने से पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पिछली सरकार के प्रयासों की आलोचना करते थे, लेकिन पिछले दशकों में भी कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है।

दिक्कत यह है कि सरकार देश में रणनीतिक ढांचे के निर्माण के लिए जिम्मेदार सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) पर ही निर्भर है। बीआरओ की कार्यशैली में कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं दिखाई देता है। चीन ने जिस रफ्तार में अपने इलाके में ऑल वेदर मेटालिक रोड और अधोसंरचना खड़े किये, बीआरओ उसके मुक़ाबिल कछुआ गति से आगे बढ़ता रहा है। बीआरओ में कुशल कर्मियों की कमी एक बड़ा मुद्दा रहा है। ऐसे में पूरे बॉर्डर लाइन पर चीनी तैयारी के मुक़ाबले हम कब गंभीर होंगे? इस सवाल पर विमर्श ज़रूरी है।

प्रेरणा

सपनों की उड़ानः दृढ़ संकल्प से बदलती है तकदीर

जीवन में सफलता प्राप्त करने वाले अधिकांश लोगों की कहानी किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि छोटे-छोटे प्रयासों, अटूट विश्वास और निरंतर सीखने की प्रवृत्ति से शुरू होती है। दुनिया में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं, जिन्होंने साधारण परिस्थितियों में जन्म लेकर अपने कर्मों के बल पर असाधारण ऊंचाइयों को छुआ। उनके पास न धन था, न विशेष सुविधाएं और न ही कोई बड़ा सहारा। फिर भी उन्होंने अपने भीतर की जिज्ञासा, परिश्रम और धैर्य को कभी समाप्त नहीं होने दिया। यही गुण उन्हें भीड़ से अलग बनाते हैं। वास्तव में सफलता उन्हीं लोगों के कदम चूमती है, जो परिस्थितियों का रोना रोने के बजाय उपलब्ध अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग करना जानते हैं। इतिहास के महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे का जीवन इसी सत्य का जीवंत प्रमाण है कि यदि मन में सीखने की ललक और कुछ कर दिखाने का संकल्प हो, तो साधारण व्यक्ति भी पूरी दुनिया को नई दिशा दे सकता है। माइकल फैराडे का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि नियमित और उच्च शिक्षा प्राप्त करना उनके लिए संभव नहीं था। बचपन से ही उन्हें जीवन की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्होंने कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया। उन्हें लंदन की एक छोटी-सी पुस्तक बांधने की दुकान में नौकरी मिली। उनका काम ग्राहकों की पुरानी और नई पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाना, फटे हुए पन्नों को ठीक करना, पुस्तकों को व्यवस्थित रखना और दुकान के अन्य छोटे-मोटे कार्य करना था। देखने में यह एक साधारण नौकरी थी, लेकिन फैराडे ने इसे केवल जीविका का साधन नहीं माना। उन्होंने इसे ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम बना लिया। दुकान में प्रतिदिन अनेक प्रकार की पुस्तकें आती थीं। साहित्य, इतिहास, दर्शन, गणित और विज्ञान जैसे विषयों की पुस्तकें उनके हाथों से गुजरती थीं। जहां दूसरे कर्मचारी केवल अपना काम पूरा करके घर चले जाते थे, वहीं फैराडे हर पुस्तक में छिपे ज्ञान को जानने का प्रयास करते थे। विशेष रूप से विज्ञान की पुस्तकें उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करती थीं। जब भी समय मिलता, वे सावधानी से उन पुस्तकों के पन्ने पढ़ते। कई वैज्ञानिक सिद्धांत उनकी समझ से बाहर होते, फिर भी वे हार नहीं मानते। वे बार-बार पढ़ते, सोचते और अपनी समझ विकसित करते। उनके भीतर यह विश्वास था कि ज्ञान किसी विद्यालय की चारदीवारी तक सीमित नहीं है। यदि मन में सीखने की सच्ची इच्छा हो, तो हर पुस्तक एक शिक्षक बन सकती है। धीरे-धीरे विज्ञान के प्रति उनका प्रेम और गहरा होता गया। वे केवल पढ़ने तक सीमित नहीं रहे। महत्वपूर्ण बातों को अपनी डायरी में लिखते, कठिन शब्दों का अर्थ खोजते और जो समझ में नहीं आता, उस पर लंबे समय तक विचार करते। यही आदत उन्हें सामान्य लोगों से अलग बनाती गई। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि उनके पास डिग्री नहीं है या वे किसी प्रतिष्ठित संस्थान में नहीं पढ़े। वे जानते थे कि वास्तविक शिक्षा जिज्ञासा और निरंतर अभ्यास से प्राप्त होती है। एक दिन उन्हें उस समय के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हम्फ्री डेवी का सार्वजनिक व्याख्यान सुनने का अवसर मिला। यह अवसर उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ। व्याख्यान के दौरान फैराडे पूरे ध्यान से प्रत्येक शब्द सुनते रहे। उन्होंने अत्यंत व्यवस्थित ढंग से विस्तृत नोट्स तैयार किए। व्याख्यान समाप्त होने के बाद भी उनका उत्साह कम नहीं हुआ। कई दिनों तक वे उन नोट्स को साफ-सुथरे ढंग से लिखते रहे। पुस्तक बांधने की कला में निपुण होने के कारण उन्होंने उन नोट्स को सुंदर रूप देकर एक पुस्तक जैसा बना दिया। इसके साथ उन्होंने हम्फ्री डेवी के नाम एक विनम्र पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी सबसे बड़ी इच्छा व्यक्त की—"मैं विज्ञान सीखना चाहता हूं और यदि मुझे अवसर मिले, तो मैं पूरी निष्ठा और मेहनत से कार्य करूंगा।"

पत्र भेजने के बाद कई सप्ताह बीत गए। कोई उत्तर नहीं आया। ऐसी स्थिति में अधिकांश लोग निराश होकर अपने सपनों को छोड़ देते हैं, लेकिन फैराडे ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने धैर्य बनाए रखा। वे पहले की तरह पुस्तकें पढ़ते रहे, काम करते रहे और स्वयं को लगातार बेहतर बनाते रहे। उन्हें विश्वास था कि यदि प्रयास सच्चा है, तो उसका परिणाम अवश्य मिलेगा।

कुछ समय बाद एक दिन अचानक संदेश आया कि हम्फ्री डेवी उनसे मिलना चाहते हैं। यह समाचार उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। जब वे डेवी से मिले, तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने उनके द्वारा तैयार किए गए नोट्स को बड़े ध्यान से देखा। नोट्स की स्पष्टता, विषय की समझ और सीखने के प्रति उनका समर्पण देखकर डेवी अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि यह युवक केवल नौकरी पाने की इच्छा नहीं रखता, बल्कि विज्ञान के प्रति वास्तविक प्रेम रखता है। कुछ समय बाद डेवी की प्रयोगशाला में सहायक का एक छोटा-सा पद खाली हुआ। उन्होंने फैराडे को वहां नियुक्त कर लिया। यह पद कोई प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पद नहीं था। उनका मुख्य कार्य प्रयोगशाला की सफाई करना, शीशियों को धोना, उपकरणों को व्यवस्थित रखना और वरिष्ठ वैज्ञानिकों की सहायता करना था। बहुत से लोग ऐसे कार्य को महत्वहीन समझते, लेकिन फैराडे ने हर जिम्मेदारी को सीखने का अवसर माना। वे प्रयोगशाला में होने वाले प्रत्येक प्रयोग को ध्यान से देखते, वैज्ञानिकों की बातचीत सुनते और हर नई जानकारी को अपने अनुभव का हिस्सा बनाते।

समय के साथ उनकी समझ और अनुभव दोनों बढ़ते गए। उन्होंने केवल दूसरों के निर्देशों का पालन नहीं किया, बल्कि स्वयं प्रयोग करने शुरू किए। वे घंटों तक वैज्ञानिक सिद्धांतों पर काम करते, गलतियों से सीखते और लगातार अपने ज्ञान को विस्तृत करते रहे। उनका मानना था कि असफलता भी सीखने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यही सोच उन्हें निरंतर आगे बढ़ाती रही।

वर्षों की कठिन साधना और अथक परिश्रम के बाद माइकल फैराडे ने विद्युत और चुंबकत्व के क्षेत्र में ऐसे ऐतिहासिक अनुसंधान किए, जिन्होंने पूरी दुनिया की वैज्ञानिक सोच बदल दी। विद्युतचुंबकीय प्रेरण की खोज, विद्युत मोटर और जनरेटर के मूल सिद्धांतों का विकास तथा विद्युत के व्यवहार पर उनके प्रयोग आधुनिक विज्ञान की आधारशिला बन गए। आज दुनिया में बिजली उत्पादन, उद्योग, परिवहन, चिकित्सा उपकरण, संचार प्रणाली और अनगिनत आधुनिक तकनीकों का विकास जिस वैज्ञानिक आधार पर खड़ा है, उसमें फैराडे का योगदान अमूल्य माना जाता है। सबसे प्रेरणादायक बात यह है कि उन्होंने कभी अपने अभावों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया।

Vishwakhabram: Russia China Secret Military Training ने उड़ा दिए दुनिया के होश, India भी रह गया हैरान

रूस और चीन के बीच पिछले वर्ष चला गुप्त सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम अब पूरी दुनिया की चिंता का विषय बन गया है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों के जरिये सामने आए गोपनीय दस्तावेजों और यूरोपीय अधिकारियों के खुलासों ने संकेत दिया है कि यूक्रेन युद्ध के बीच रूस और चीन केवल कूटनीतिक सहयोग तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सैन्य स्तर पर भी तेजी से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि चीनी सैनिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव की व्यक्तिगत मंजूरी प्राप्त थी और इसमें दोनों देशों के कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी सीधे तौर पर शामिल थे। इन खुलासों ने यूरोप और पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ा दी है। हम आपको बता दें कि गोपनीय दस्तावेजों के अनुसार अगस्त 2025 में बेलोसोव के आंतरिक आदेश के बाद रूसी सेना का एक प्रतिनिधिमंडल चीन पहुंचा, जहां उसे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की सैन्य सुविधाओं में विशेष प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण का सबसे संवेदनशील पहलू था रेडियोलॉजिकल, रासायनिक और जैविक सुरक्षा से जुड़ा अभ्यास। नवंबर में बीजिंग स्थित एक सैन्य केंद्र में तीन सप्ताह तक चले पाठ्यक्रम में रूसी सैनिकों को रासायनिक टोही, विकिरण टोही और दूषित वातावरण में सुरक्षा तंत्र बचाने के तरीके सिखाए गए। रिपोर्टों के मुताबिक दस्तावेजों में ऐसे चित्र भी शामिल थे जिनमें चीनी प्रशिक्षक रूसी सैनिकों को मॉडल परमाणु रिएक्टर के सामने प्रशिक्षण देते दिखाई दे रहे थे।

यूरोपीय अधिकारियों का इस मामले में कहना है कि इस प्रकार के प्रशिक्षण का महत्व केवल तकनीकी नहीं बल्कि अत्यंत सामरिक है। रेडियोलॉजिकल, रासायनिक और जैविक युद्ध किसी भी आधुनिक सैन्य संघर्ष का सबसे संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में चीन द्वारा रूस को इस स्तर की जानकारी और अभ्यास उपलब्ध कराना यह संकेत देता है कि बीजिंग अब यूक्रेन युद्ध से स्वयं को पूरी तरह अलग दिखाने की नीति पर व्यवहारिक रूप से कायम नहीं है। सार्वजनिक मंचों पर चीन लगातार खुद को तटस्थ और शांति मध्यस्थ बताता रहा है, लेकिन इन खुलासों ने उसकी वास्तविक भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

रिपोर्टों के मुताबिक पिछले साल लगभग 200 रूसी सैनिकों को चीन में प्रशिक्षण दिया गया था, जिनमें से कुछ बाद में यूक्रेन युद्ध में भी शामिल हुए। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह केवल शैक्षणिक आदान प्रदान नहीं था, बल्कि युद्धक जरूरतों से सीधे जुड़ा कार्यक्रम था। देखा जाये तो रूस को यूक्रेन मोर्चे पर चार वर्षों से अधिक समय का वास्तविक युद्ध अनुभव प्राप्त हो चुका है, जबकि चीन दशकों से किसी बड़े युद्ध में शामिल नहीं रहा है। इसी कारण दोनों देशों के बीच यह साझेदारी पूरक स्वरूप लेती दिखाई दे रही है। चीन रूस से वास्तविक युद्ध अनुभव सीखना चाहता है, जबकि रूस चीन की आधुनिक तकनीक, सिमुलेटर और सैन्य उपकरणों का लाभ उठा रहा है।

हम आपको बता दें कि सामने आये दस्तावेजों में नानजिंग और बेंगबू स्थित प्रशिक्षण केंद्रों का भी उल्लेख है। रूसी रिपोर्टों में चीनी उपकरणों और प्रशिक्षकों की गुणवत्ता की प्रशंसा की गई, लेकिन साथ ही यह भी दर्ज किया गया कि चीन के पास प्रत्यक्ष युद्ध अनुभव का अभाव है। इससे दोनों सेनाओं के बीच सीखने और सिखाने का दोतरफा समीकरण उभरता है। इस कार्यक्रम में रूस की थल सेना के उप प्रमुख कर्नल जनरल रुस्तम मुरादोव ने रूसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जबकि चीन की रेडियोलॉजिकल, रासायनिक और जैविक रक्षा अकादमी के प्रमुख मेजर जनरल ली जिनसुन ने एक पाठ्यक्रम के उद्घाटन में भाग लिया। रूसी मेजर जनरल विताली गेरासिमोव भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल रहे। जुलाई में हुए समझौते पर रूसी मेजर जनरल रुस्तम खुसैनोव और चीनी वरिष्ठ कर्नल सुन दायुन के हस्ताक्षर बताए गए हैं।

देखा जाये तो यूरोपीय संघ के लिए यह घटनाक्रम विशेष चिंता का विषय बन गया है। यूक्रेन पर साल 2022 के रूसी आक्रमण के बाद से यूरोप रूस को सबसे बड़ा सुरक्षा खतरा मानता रहा है। अब चीन और रूस के बढ़ते सैन्य संबंधों ने ब्रसेल्स को नई रणनीतिक दुविधा में डाल दिया है। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काया कालास ने दावा किया है कि यूरोप ने अपने स्तर पर इस प्रशिक्षण की पुष्टि कर ली है और इसके निहितार्थों का अध्ययन किया जा रहा है। दूसरी ओर बीजिंग ने इन आरोपों को पश्चिमी दुष्प्रचार करार दिया है। इसके बावजूद यूरोपीय देशों के भीतर यह बहस तेज हो चुकी है कि क्या चीन को अब केवल व्यापारिक साझेदार के रूप में देखना पर्याप्त है या उसे रूस के युद्ध प्रयासों का निर्णायक समर्थक मानकर नई नीति बनाई जानी चाहिए?

उधर, यह घटनाक्रम वैश्विक शक्ति संतुलन में उभर रहे नए ध्रुवीकरण को भी उजागर करता है। एक ओर अमेरिका और यूरोपीय देश यूक्रेन के समर्थन में खड़े हैं, वहीं दूसरी ओर रूस और चीन रणनीतिक निकटता बढ़ा रहे हैं। यदि यह सैन्य सहयोग आगे और गहरा होता है तो भविष्य में संयुक्त सैन्य अभ्यास, हथियार विकास और सामरिक खुफिया साझेदारी जैसे नए आयाम भी सामने आ सकते हैं। इससे एशिया और यूरोप दोनों में सुरक्षा समीकरण बदल सकते हैं।

भारत के लिए भी यह घटनाक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली लंबे समय से रूस के साथ पारंपरिक रक्षा संबंध बनाए हुए है, जबकि चीन उसके लिए सबसे बड़ी सामरिक चुनौती बना हुआ है। ऐसे में रूस और चीन की बढ़ती सैन्य निकटता भारत के लिए रणनीतिक संतुलन को जटिल बना सकती है। यदि मॉस्को बीजिंग के अधिक करीब जाता है तो भविष्य में भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी, हथियार आपूर्ति और सामरिक सहयोग के स्तर पर नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। विशेषकर तब, जब चीन पहले से ही हिंद महासागर, दक्षिण एशिया और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी सैन्य सक्रियता बढ़ा रहा है।

अभियान

आस्था, इतिहास और संस्कृति का अद्भुत संगम: वह प्राचीन भारतीय नगरी जहां हर पत्थर सुनाता है सभ्यता की कहानी

भारत को मंदिरों, तीर्थों और आध्यात्मिक परंपराओं की भूमि कहा जाता है। यहां की हर दिशा में कोई न कोई ऐसा स्थान अवश्य मिलता है, जो अपनी धार्मिक मान्यताओं, ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक वैभव के कारण दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता है। हिमालय की वादियों में बसे प्राचीन धामों से लेकर दक्षिण भारत के विशाल मंदिरों तक, हर क्षेत्र अपनी अलग पहचान रखता है। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में आध्यात्मिक पर्यटन यानी स्पिरिचुअल टूरिज्म तेजी से लोकप्रिय हुआ है। अब लोग केवल प्राकृतिक सुंदरता देखने या छुट्टियां बिताने के लिए यात्रा नहीं करते, बल्कि ऐसे स्थानों की तलाश भी करते हैं जहां उन्हें मानसिक शांति, सांस्कृतिक समृद्धि और इतिहास की गहराई का अनुभव हो सके। ऐसी ही एक अद्भुत नगरी है कांचीपुरम, जिसे सदियों से "हजार मंदिरों की नगरी" के नाम से जाना जाता है। यह केवल एक शहर नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, स्थापत्य कला, धार्मिक आस्था और प्राचीन ज्ञान परंपरा का जीवंत संग्रहालय है।

दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित कांचीपुरम का इतिहास दो हजार वर्षों से भी अधिक पुराना माना जाता है। यह शहर कभी पल्लव साम्राज्य की राजधानी था और बाद में चोल, विजयनगर तथा अन्य शक्तिशाली राजवंशों के संरक्षण में लगातार विकसित होता रहा। विभिन्न शासकों ने यहां भव्य मंदिरों, सरोवरों, मठों और सांस्कृतिक केंद्रों का निर्माण कराया। यही कारण है कि यह शहर केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास और वास्तुकला के अध्ययन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्राचीन काल में इसे शिक्षा और दर्शन का प्रमुख केंद्र भी माना जाता था, जहां देश-विदेश से विद्वान अध्ययन और आध्यात्मिक साधना के लिए आते थे।

कांचीपुरम को "सिटी ऑफ थाउजेंड टेम्पल्स" अर्थात हजार मंदिरों का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक समय यहां लगभग एक हजार छोटे-बड़े मंदिर मौजूद थे। समय के साथ अनेक मंदिर प्राकृतिक आपदाओं, युद्धों और समय की मार के कारण नष्ट हो गए, लेकिन आज भी यहां सौ से अधिक प्राचीन और भव्य मंदिर सुरक्षित हैं। इन मंदिरों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी अद्भुत वास्तुकला, विशाल गोपुरम, बारीक पत्थर की नक्काशी और धार्मिक महत्व है। यहां का हर मंदिर अपनी अलग कहानी कहता है और भारतीय शिल्पकला की उत्कृष्टता का प्रमाण प्रस्तुत करता है।

कांचीपुरम के मंदिरों में प्रवेश करते ही ऐसा अनुभव होता है मानो समय कई शताब्दियों पीछे लौट गया हो। विशाल पत्थरों से निर्मित ऊंचे प्रवेश द्वार, लंबी परिक्रमा पथ, कलात्मक स्तंभ, सुंदर मंडप और देवताओं की बारीक मूर्तियां देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। यहां के मंदिर केवल पूजा-अर्चना के स्थान नहीं हैं, बल्कि वे भारतीय मूर्तिकला, स्थापत्य विज्ञान, ज्यामिति, खगोल विज्ञान और सांस्कृतिक जीवन के जीवंत दस्तावेज भी हैं। इन मंदिरों के निर्माण में जिस सूक्ष्मता और कलात्मकता का परिचय दिया गया है, वह आज भी आधुनिक इंजीनियरों और इतिहासकारों को आश्चर्यचकित कर देता है।

कांचीपुरम का सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर कैलाशनाथर मंदिर है, जिसका निर्माण आठवीं शताब्दी में पल्लव शासकों ने कराया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे द्रविड़ शैली की वास्तुकला का प्रारंभिक एवं उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियां, देवी-देवताओं की आकृतियां, नृत्य मुद्राएं और धार्मिक कथाओं का चित्रण अद्भुत कलात्मकता का परिचय देते हैं। यहां आने वाले पर्यटक केवल दर्शन ही नहीं करते, बल्कि घंटों तक इस मंदिर की स्थापत्य कला को निहारते रहते हैं।

इसी प्रकार एकम्बरेश्वर मंदिर भी कांचीपुरम की पहचान है। भगवान शिव को समर्पित यह विशाल मंदिर अपने ऊंचे गोपुरम, विस्तृत परिसर और प्राचीन आम के वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यता है कि इस वृक्ष की आयु हजारों वर्ष पुरानी है और इसके नीचे माता पार्वती ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। मंदिर का विशाल प्रांगण, लंबे स्तंभों वाले मंडप और धार्मिक अनुष्ठानों का वातावरण श्रद्धालुओं को गहरे आध्यात्मिक अनुभव से भर देता है।

कांचीपुरम का कामाक्षी अम्मन मंदिर भी विशेष महत्व रखता है। यह देवी शक्ति को समर्पित प्रमुख मंदिरों में से एक माना जाता है। देशभर से लाखों श्रद्धालु यहां माता कामाक्षी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। धार्मिक परंपरा के अनुसार यह शक्तिपीठों से जुड़ा अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है। मंदिर में होने वाली दैनिक पूजा, विशेष आरती और वार्षिक उत्सव श्रद्धालुओं के मन में गहरी आस्था का संचार करते हैं। नवरात्रि और अन्य धार्मिक अवसरों पर यहां का वातावरण अत्यंत दिव्य और भव्य हो जाता है।

कांचीपुरम की एक और विशेषता यह है कि यहां शैव और वैष्णव दोनों परंपराओं के अनेक प्रसिद्ध मंदिर मौजूद हैं। जहां एक ओर भगवान शिव के भव्य मंदिर हैं, वहीं दूसरी ओर भगवान विष्णु को समर्पित अनेक प्राचीन मंदिर भी स्थित हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह नगर सदियों से विभिन्न धार्मिक परंपराओं के समन्वय और सहअस्तित्व का प्रतीक रहा है। यहां आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु अपनी आस्था के अनुसार पूजा-अर्चना कर सकता है और भारतीय संस्कृति की विविधता को निकट से महसूस कर सकता है।

कांचीपुरम केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह भारतीय दर्शन और शिक्षा का भी ऐतिहासिक केंद्र रहा है। प्राचीन काल में यहां अनेक गुरुकुल, मठ और विद्या संस्थान संचालित होते थे। वेद, उपनिषद, संस्कृत साहित्य, दर्शन, गणित और ज्योतिष जैसे विषयों का अध्ययन यहां बड़े स्तर पर किया जाता था। कई महान विद्वानों और संतों ने यहां रहकर भारतीय ज्ञान परंपरा को समृद्ध किया। यही कारण है कि इस शहर को आध्यात्मिक राजधानी के साथ-साथ ज्ञान की भूमि भी कहा जाता है।

यदि कोई व्यक्ति आधुनिक शहरों की भागदौड़, शोर-शराबे और तनावपूर्ण जीवन से कुछ समय के लिए दूर जाकर मानसिक शांति की तलाश करना चाहता है, तो कांचीपुरम उसके लिए आदर्श स्थान साबित हो सकता है। यहां का शांत वातावरण, मंदिरों में गूंजती घंटियों की मधुर ध्वनि, धूप और चंदन की सुगंध, वैदिक मंत्रों का उच्चारण तथा श्रद्धालुओं की सादगी मन को गहरी शांति प्रदान करती है। यहां आने वाले अनेक लोग बताते हैं कि इस शहर में प्रवेश करते ही उन्हें एक अलग प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है।

कांचीपुरम की गलियां भी अपने आप में विशेष आकर्षण रखती हैं। यहां पारंपरिक दक्षिण भारतीय जीवनशैली आज भी जीवित दिखाई देती है। पुराने घर, स्थानीय बाजार, मंदिरों के आसपास की दुकानें, पारंपरिक भोजन और लोगों की सरल जीवनशैली पर्यटकों को भारतीय संस्कृति की वास्तविक झलक दिखाती है। यहां घूमते हुए ऐसा लगता है मानो आधुनिकता और परंपरा एक साथ कदम मिला रही हों।

इस शहर का नाम आते ही प्रसिद्ध कांजीवरम रेशमी साड़ियों का उल्लेख अवश्य होता है। दुनिया भर में अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ता, सुंदर डिजाइन और शुद्ध रेशम के लिए प्रसिद्ध कांजीवरम साड़ियां भारतीय हस्तशिल्प की अमूल्य धरोहर मानी जाती हैं। इन साड़ियों को तैयार करने में कुशल कारीगर कई दिनों से लेकर कई सप्ताह तक मेहनत करते हैं। सुनहरे जरी के काम, पारंपरिक डिजाइनों और चमकदार रंगों के कारण इन साड़ियों की मांग भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत अधिक है। कांचीपुरम आने वाले अधिकांश पर्यटक यहां की प्रसिद्ध साड़ियों की खरीदारी अवश्य करते हैं, क्योंकि यह केवल एक वस्त्र नहीं बल्कि दक्षिण भारतीय संस्कृति और शिल्पकला का प्रतीक है।

यहां का स्थानीय भोजन भी पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करता है। पारंपरिक दक्षिण भारतीय व्यंजन जैसे इडली, डोसा, पोंगल, उत्तपम, सांभर, नारियल की चटनी और फिल्टर कॉफी का स्वाद यात्रियों के अनुभव को और भी यादगार बना देता है। स्थानीय भोजन में सादगी के साथ-साथ पोषण और स्वाद का सुंदर संतुलन देखने को मिलता है।

कांचीपुरम वर्षभर पर्यटकों का स्वागत करता है, लेकिन अक्टूबर से मार्च के बीच यहां का मौसम सबसे अधिक सुहावना रहता है। इस दौरान मंदिरों में विभिन्न धार्मिक उत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं, जिससे शहर की भव्यता और भी बढ़ जाती है। यदि कोई व्यक्ति यहां की वास्तविक संस्कृति को करीब से देखना चाहता है, तो त्योहारों के समय की यात्रा उसके लिए अविस्मरणीय अनुभव बन सकती है।

आज जब दुनिया तेजी से आधुनिकता की ओर बढ़ रही है, तब कांचीपुरम जैसे शहर हमें अपनी जड़ों से जोड़ने का कार्य करते हैं।

PRGI NO. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002 and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

भारत के सेमीकॉन मिशन में एक और सफलता : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 4 जुलाई को साणंद में सेमीकंडक्टर ओएसएटी प्लांट में चिप के व्यावसायिक उत्पादन का शुभारंभ करेंगे

- भारत की सीजी सेमी द्वारा ओएसएटी फैसिलिटी का निर्माण, प्रधानमंत्री द्वारा व्यावसायिक उत्पादन के लॉन्च के बाद साणंद से देश-विदेश तक पहुंचेंगे यह चिप्स
- 7600 करोड़ रुपए का निवेश, 300 कर्मचारी कार्यरत, अगले पांच वर्ष में 5 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार
- साणंद आज ग्लोबल मैप पर सेमीकंडक्टर हब के रूप में उभर रहा है, यह दशक भारत के टेक-फ्यूचर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

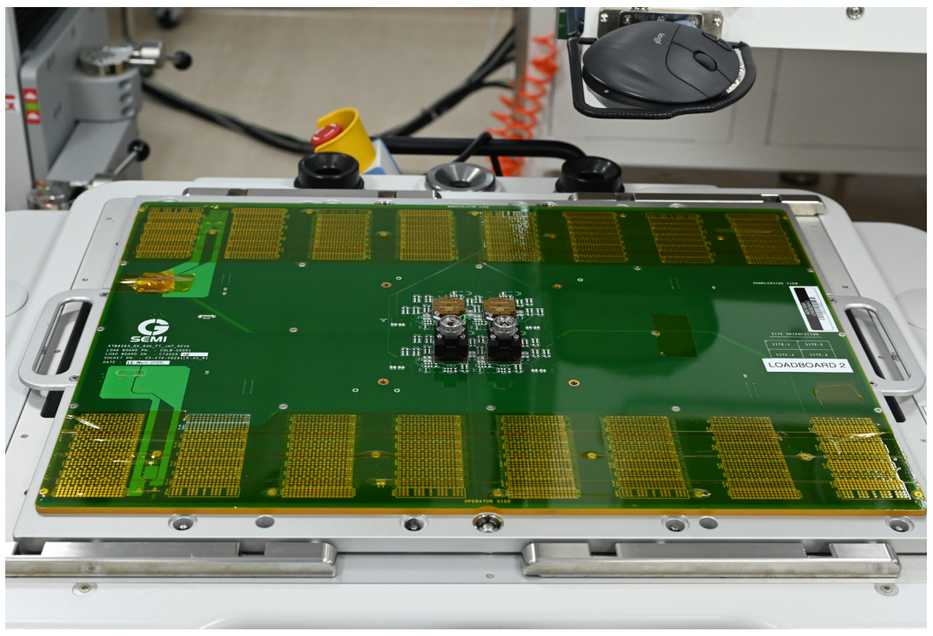

गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी शनिवार, 4 जुलाई 2026 को साणंद में सीजी सेमी की आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट (ओएसएटी) सुविधा का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री के करकमलों से लॉन्च के बाद यह कंपनी देश और दुनिया में अपने ग्राहकों को सेमीकंडक्टर चिप्स भेजेगी। भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत इस प्रोजेक्ट को केंद्रीय कैबिनेट ने फरवरी, 2024 में मंजूरी दी थी।

सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी सीजी सेमी प्रा. लिमिटेड ने 7600 करोड़ रुपए की लागत से साणंद में ओएसएटी फैसिलिटी शुरू की है। सीजी सेमी के साथ जापान की रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स और थाइलैंड की स्टार माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स की संयुक्त भागीदारी है। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से साणंद में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम और भी मजबूत होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के अनुसार भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विकास से यह दशक टेक-फ्यूचर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा।

माइक्रोन प्लांट के शुभारंभ के बाद केन्स सेमीकॉन और अब सीजी सेमी द्वारा ओएसएटी फैसिलिटी शुरू होने से स्थानीय आर्थिक विकास को बूस्ट मिलेगा। ओएसएटी यानी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट प्लांट में चिप की टेस्टिंग और पैकेजिंग करके उसे बाजार में पहुंचाने का काम पूरा किया जाता है। सीजी सेमी द्वारा दूसरे एक प्लांट के निर्माण का काम भी अभी प्रगति पर है। ये दोनों ओएसएटी फैसिलिटीज साथ मिलकर प्रतिदिन कुल 1.5 करोड़ चिप्स का निर्माण करेंगी।

प्रधानमंत्री 4 जुलाई को सीजी सेमी की ओएसएटी फैसिलिटी में विभिन्न सेमीकंडक्टर प्रक्रियाओं का निरीक्षण करेंगे। इस अवसर पर उनके साथ केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया मौजूद रहेंगे। ओएसएटी फैसिलिटी के शुभारंभ के बाद प्रधानमंत्री एक सभा को संबोधित करेंगे।

इस ओएसएटी फैसिलिटी में क्यूएफएन (क्वाड फ्लैट नो-लीड) और क्यूएफपी (क्वाड फ्लैट पैकेज) जैसी लिगेसी चिप्स और आधुनिक एफसी-बीजीए (फ्लिप चिप बॉल ग्रिड ऐरे) और एफसी-सीएसपी (फ्लिप चिप-चिप स्केल पैकेज) चिप्स का निर्माण किया जाएगा, जो ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल उपकरणों, 5जी उपकरणों और पावर एप्लीकेशन क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करेगी।

कंपनी में अभी 300 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। प्लांट शुरू होने के बाद अगले पांच वर्षों में 5000 प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार अवसरों का सृजन होगा।

हमारा लक्ष्य केवल फैक्ट्री स्थापित करने तक सीमित नहीं है : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री ने साफ कहा है, "हमारा लक्ष्य केवल एक फैक्ट्री स्थापित करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण इकोसिस्टम बनाना है। भारत अब सेमीकंडक्टर की पूरी वैल्यू चेन पर फोकस कर रहा है, जिसमें डिजाइन इंजीनियर से लेकर मशीन निर्माता और लॉजिस्टिक्स तक के सभी स्तर शामिल हैं। 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0' की घोषणा इसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। जैसे-जैसे उत्पादन बढ़ेगा, वैसे-वैसे भारत के अंदर ही मटेरियल और कंपोनेंट्स की मांग भी बढ़ेगी, जो स्थानीय उद्योगों के लिए सबसे बड़ा अवसर होगा।"

सेमीकॉन इंडिया के तहत गुजरात में 6 प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी

भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को आगे बढ़ाने में गुजरात अग्रणी भूमिका निभा रहा है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए गुजरात ने सबसे पहले समर्पित सेमीकंडक्टर पॉलिसी घोषित की थी। अभी, सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 6 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इन प्रोजेक्ट्स में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोन टेक्नोलॉजी, सीजी सेमी, केन्स सेमीकॉन, सुची सेमीकॉन और क्रिस्टल मैट्रिक्स शामिल हैं। इस सेक्टर में इन 6 प्रोजेक्ट्स के जरिए कुल 14.7 बिलियन डॉलर का निवेश हो रहा है। फरवरी, 2026 में माइक्रोन टेक्नोलॉजी की एटीएमपी (असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग) फैसिलिटी और मार्च 2026 में केन्स सेमीकॉन की ओएसएटी फैसिलिटी में कामकाज की शुरुआत भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए एक अहम कदम था। हाल ही में, सुची सेमीकॉन और क्रिस्टल मैट्रिक्स को भी नई सेमीकंडक्टर इकाइयां लगाने की मंजूरी मिली है। ये प्रोजेक्ट्स भारत में सेमीकंडक्टर उत्पादन को बूस्ट देंगे और एक प्रमुख सेमीकंडक्टर हब के रूप में गुजरात की स्थिति को मजबूत करेंगे।

साणंद : ऑटो हब से सेमीकंडक्टर हब तक

बहुत ही कम समय में साणंद के औद्योगिक विकास में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला है। माइक्रोन टेक्नोलॉजी, केन्स सेमीकॉन के बाद अब सीजी सेमी द्वारा भी यहां सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित किया गया है। एक समय ऑटोमोबाइल हब के रूप में जाना जाने वाला साणंद अब भारत के पहले चिप पैकेजिंग क्लस्टर और वैश्विक सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है। साणंद ताइवान के सिंशु शहर और दक्षिण कोरिया के ग्योंगी शहर के समान भारत में सेमीकंडक्टर हब के रूप में विकसित हो रहा है।

माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात अब केवल निवेश स्थल के रूप में ही पहचाना नहीं जाता। अब, गुजरात उससे आगे बढ़कर उत्पादन, डिजाइन, पैकेजिंग, सप्लाई चेन, कौशल विकास, अनुसंधान, लॉजिस्टिक्स और नवाचार के साथ एक सर्वग्राही इकोसिस्टम बन गया है। गुजरात सरकार ने मजबूत नीतियों, आधुनिक बुनियादी ढांचे, तेज मंजूरी और व्यवसाय-अनुकूल गवर्नेंस के माध्यम से सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास को लगातार समर्थन दिया है। प्रोजेक्ट के आयोजन से लेकर उत्पादन शुरू करने तक, राज्य द्वारा ऐसा वातावरण उपलब्ध कराया जाता है, जो निवेश को प्रोत्साहन देने के साथ ही वैश्विक भरोसे का निर्माण भी करता है।

गुजरात सरकार का ऐतिहासिक किसानोन्मुखी निर्णय बिजली टावर तथा लाइन मुआवजे में भारी वृद्धि

- जंत्री के बजाय अब बाजार भाव से दोगुने दर पर मुआवजा दिया जाएगा
- टावर बेस क्षेत्र की गणना में चारों ओर अतिरिक्त एक-एक मीटर जोड़ा गया, 765 केवी लाइन में 625 वर्गमीटर के बजाय 729 वर्गमीटर का मुआवजा दिया जाएगा।
- भूमि का वास्तविक बाजार मूल्य तय करने के लिए 'मार्केट रेट कमेटी' (एमआरसी) का गठन होगा; किसान प्रतिनिधियों को मिलेगा स्थान
- पूर्व में तीन चरणों में भुगतान होता था, अब एक साथ शुरुआत में ही 100 प्रतिशत भुगतान

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में तथा उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी के मार्गदर्शन में कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी, ऊर्जा मंत्री श्री ऋषिकेशभाई पटेल और ऊर्जा राज्य मंत्री श्री कौशिकभाई वेकरिया ने किसानों के साथ चर्चा, विचार-विमर्श एवं परामर्श करके तथा किसानों के आर्थिक हित को सर्वोपरि रखते हुए एक महत्वपूर्ण एवं उदार निर्णय लिया है। खेतों से गुजरने वाली बिजली लाइन तथा बिजली टावर स्थापित किए जाने के बदले किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे में सरकार ने वृद्धि करने की घोषणा की है। इस निर्णय से राज्य के लाखों किसानों को उनकी भूमि का उचित एवं बाजार आधारित मुआवजा मिलेगा।

किसानों के खेतों से गुजरने वाली बिजली लाइन के लिए अब तक खेत में बिजली पोल-खंभे अथवा लाइन डालने के बदले किसानों को जंत्री की दोगुनी दर (200 प्रतिशत) के हिसाब से मुआवजे का भुगतान किया जाता था। इस संबंध में विभिन्न किसान संगठनों से प्राप्त प्रस्तुतियों के तहत मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल द्वारा बड़ा सुधार करते हुए जंत्री आधारित नहीं, बल्कि भूमि के प्रचलित बाजार भाव (मार्केट रेट) के दोगुने मूल्य का भुगतान करने का किसान-हितैषी निर्णय किया गया है।

इसके अतिरिक्त; अब तक खेत में स्थापित किए जाने वाले बिजली टावर के बेस (नींव) क्षेत्र के वास्तविक माप के अनुसार ही मुआवजा दिया जाता था। अब से किसानों के लाभ के लिए टावर के बेस क्षेत्र की प्रत्येक दिशा में अतिरिक्त एक-एक मीटर जोड़कर अधिक मुआवजा दिया जाएगा। उदाहरण के लिए; 765 केवी लाइन में पहले 625 वर्गमीटर के हिसाब से मुआवजा दिया जाता था, जिसे अब से प्रत्येक दिशा में अतिरिक्त एक मीटर जोड़ते हुए बढ़ाकर 729 वर्गमीटर के हिसाब से दिया जाएगा।

पूर्व में जमीन मालिकों को मुआवजे के संबंध में फाउंडेशन चरण में 40 प्रतिशत, इरेक्शन के समय 40 प्रतिशत तथा तार बिछाने के बाद 20 प्रतिशत के अनुसार भुगतान किया जाता था। अब इसके स्थान पर जमीन मालिकों को एकमुश्त तथा कार्य शुरू होने से पहले ही 100 प्रतिशत मुआवजा देने का निश्चय किया गया है। किसानों की भूमि का वास्तविक बाजार मूल्य तटस्थ एवं पारदर्शी ढंग से निर्धारित हो सके; इसके लिए राज्य सरकार द्वारा बाजार दर समिति (एमआरसी) का गठन किया जाएगा। विशेष बात यह है कि इस समिति में प्रभावित किसानों के प्रतिनिधि तथा किसानों के अधिकृत मार्केट वैल्यूअर को भी स्थान दिया जाएगा, जिससे किसानों के साथ अन्याय न हो। मार्केट रेट निर्धारित करने वाली समिति में कलेक्टर, भूमि मालिकों के प्रतिनिधि तथा ट्रांसमिशन सर्विस प्रोवाइडर के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। दूसरी ओर; बिजली लाइन के राइट ऑफ वे कॉरिडोर के लिए एमआरसी द्वारा निर्धारित हुए बाजार मूल्य के आधार पर क्षेत्रानुसार मुआवजा दिया जाएगा। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में बाजार मूल्य का 30 प्रतिशत, नगर पालिका क्षेत्र में बाजार मूल्य का 45 प्रतिशत और महानगर पालिका क्षेत्र में बाजार मूल्य का 60 प्रतिशत मुआवजे के रूप में दिया जाएगा।

राज्य सरकार ने इस निर्णय में उदारता दिखाते हुए स्पष्ट किया है कि जिन किसानों ने पहले पुराने दाम के अनुसार मुआवजा प्राप्त कर लिया है, परंतु बिजली लाइन का कार्य अभी प्रगति पर है; ऐसे सभी किसानों को भी इस नीति का लाभ देय होगा।

छगनलाल मेवाड़ा का पत्रकारिता पर बढ़ते खतरों पर लेख, अनैतिक व्यवसायों के खिलाफ आवाज उठाने की अपील

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत

पत्रकारिता जगत, जिसे विश्व का चौथा स्तंभ माना जाता है, वर्तमान में संकट में है। पत्रकारिता जगत से जुड़ा व्यक्ति पत्रकार होता है। उसका काम जनता की समस्याओं को आवाज़ देना, निडरता और साहस से प्रेस के माध्यम से जनता के साथ हो रहे अन्याय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। मौजूद बुराइयों में शराब और जुआ, अनैतिक व्यापार, नशीली दवाएं, गांजा, चरस, मादक पदार्थ और अन्य ऐसे धंधे शामिल हैं जिन्होंने मानव जगत में तबाही मचा रखी है। ऐसे कृत्यों को उजागर करना एक सच्चे और ईमानदार पत्रकार का कर्तव्य है।

समाज में चल रही अनैतिक गतिविधियों को उजागर करना और पुलिस को इसकी जानकारी देना पत्रकारों का काम है। पत्रकार ही किसी स्थान पर हो रही अनैतिक गतिविधियों को कैमरे में कैद करते हैं या वीडियो के माध्यम से अपराधियों को बेनकाब करते हैं, और आम जनता को पीड़ा पहुंचाने वाले अपराधियों का पर्दाफाश करते हैं। इससे पुलिस और सरकार को प्रेस रिपोर्टों और समाचार चैनलों के माध्यम से उचित कार्रवाई करने और ऐसे अनैतिक कृत्यों को अंजाम देने वालों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

तो यहाँ सवाल उठता है कि क्या शराबखोरी, जुआ, अनैतिकता या किसी भी अन्य अवैध गतिविधि जैसी सामाजिक बुराइयों को उजागर करना अपराध है? क्या पुलिस का ध्यान ऐसी गतिविधियों की ओर आकर्षित करने के लिए अखबार के माध्यम से रिपोर्ट प्रकाशित करना अपराध है? यदि रिपोर्ट प्रकाशित करना अपराध है, तो अखबार को कानूनी नोटिस भेजें और अदालत में मामला ले जाएं, अदालत खुली है। लेकिन किसी पत्रकार पर हमला करना या उसके परिवार को डराना-धमकाना किस हद तक उचित है?

और यदि किसी को लगता है कि हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा है या समाज में हमारा अपमान हुआ है, तो उन्हें कानूनी तौर पर समाचार पत्र को नोटिस भेजना चाहिए। न्यायालय समाचार पत्र के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दायर करने के लिए खुला है।

नासिरनगर विध्वंस: पुलिस तैनाती, एसओजी तैनाती और मंजूरी पर सवाल उठे

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा)

जब पुलिस सुरक्षा के लिए आवेदन पुलिस आयुक्त के पास मंजूरी के लिए जाता है, तो क्या नासिर नगर विध्वंस की सुरक्षा संबंधी फाइल पुलिस आयुक्त तक पहुंची है या नहीं? आम तौर पर, पुलिस सुरक्षा संबंधित विध्वंस क्षेत्र के पुलिस स्टेशन द्वारा आवंटित की जाती है। तो नासिर नगर के लिए एसओजी की विशेष सुरक्षा की क्या आवश्यकता है?

अगर नगर आयुक्त को वाकई जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने झूठे बयान क्यों दिए? केंद्रीय क्षेत्र के अधिकारी इतने मूर्ख नहीं हैं कि नगर आयुक्त या क्षेत्र प्रमुख की अनुमति के बिना इधर-उधर भागते फिरें।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भेजे गए ई-मेल के बाद अहमदाबाद में ऐतिहासिक स्टीम इंजन 'प्रगति' के संरक्षण का अवसर मिला

एक ई-मेल से शुरू हुई पहल ने भारतीय रेल की ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण का रूप ले लिया। Concepts Innovative के प्रोपराइटर टी. के. रवीन्द्रन ने 1 दिसंबर 2025 को रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव को ई-मेल भेजकर अपनी अभिनव MULTYBOND कोटिंग तकनीक को भारतीय रेलवे में उपयोग करने का प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव में रेलवे कोचों एवं धातु संरचनाओं के लिए वॉटरप्रूफिंग, जंग-रोधी सुरक्षा, हीट रिडक्शन और ऊर्जा दक्षता से जुड़े समाधान प्रस्तुत किए गए थे।

रेल मंत्री द्वारा इस प्रस्ताव पर संज्ञान लिया। जिसके बाद पश्चिम रेलवे में अहमदाबाद मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश ने इस तकनीक का ट्रायल करने के निर्देश दिए। इसके बाद ट्रायल के लिए मण्डल कार्यालय परिसर में स्थापित ऐतिहासिक 'प्रगति' (ZD Class Meter Gauge Steam Locomotive No. 548) का चयन किया गया।

वर्ष 1957 में जापान की Nippon Sharyo द्वारा निर्मित 'प्रगति' स्टीम लोकोमोटिव भारतीय रेल की गौरवशाली विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वर्ष 2008 से यह अहमदाबाद मंडल के डीआरएम कार्यालय परिसर में प्रदर्शित है। वर्षों तक खुले वातावरण में रहने के कारण इंजन पर जंग, धूप, वर्षा और अन्य पर्यावरणीय प्रभाव दिखाई देने लगे थे। इसके संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण के लिए MULTYBOND कोटिंग तकनीक का उपयोग किया गया।

कंपनी का कहना है कि MULTYBOND एक विशेष सुरक्षात्मक कोटिंग है, जो धातु संरचनाओं को जंग, नमी, फफूंद और मौसम के दुष्प्रभावों से बचाने के साथ-साथ हीट रिडक्शन, लीकेज नियंत्रण, ऊर्जा दक्षता और सतह की दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसका उपयोग रेलवे के अलावा पुलों, औद्योगिक इकाइयों, जल टंकियों, भवनों और अन्य धातु एवं कंक्रीट संरचनाओं पर भी किया जा सकता है। कंपनी के अनुसार वह पिछले एक दशक से अधिक समय से इस तकनीक पर कार्य कर रही है और विभिन्न सरकारी एवं निजी संस्थानों में इसके सकारात्मक परिणाम मिले हैं। कंपनी का दावा है कि उसके प्रमुख ग्राहकों में ब्रह्माकुमारी मुख्यालय (आबू रोड), वडोदरा पुलिस आयुक्त कार्यालय, वडोदरा सेंट्रल जेल, AVT Group (केरल), वडोदरा एयरपोर्ट तथा Indus Fire Safety Pvt. Ltd. जैसे संस्थान शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कई निजी संस्थानों एवं व्यक्तिगत ग्राहकों ने भी इस तकनीक का उपयोग किया है।

ऐतिहासिक 'प्रगति' स्टीम लोकोमोटिव पर किया गया यह संरक्षण कार्य भारतीय रेल की विरासत को सुरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। यह पहल दर्शाती है कि नवाचार, स्वदेशी तकनीक और प्रशासनिक सहयोग के माध्यम से रेलवे की ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण आधुनिक और टिकाऊ तरीके से किया जा सकता है।

नई दिल्ली में सूरत के ज्योतिषी राजू महाराज को सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी का पुरस्कार मिला

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत

सूरत के प्रसिद्ध और लोकप्रिय ज्योतिषी राजू महाराज को देश की राजधानी नई दिल्ली में सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी का पुरस्कार मिला है। सूरत, गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य शहरों में अनेक शिष्यों वाले राजू महाराज ज्योतिष के विशेषज्ञ हैं। उनके परामर्श और मार्गदर्शन से कई परिवार सुखमय जीवन जी रहे हैं।

शांत और सरल स्वभाव के राजू महाराज से मिलने पर लोगों में खुशी और उत्साह का भाव उत्पन्न होता है। उनके मार्गदर्शन और ज्योतिषीय शक्ति से लोगों के दुख-दर्द दूर होते हैं। सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी का पुरस्कार प्राप्त करने के बाद, गुजरात प्रदेश नगर निगम कर्मचारी कांग्रेस के अध्यक्ष, जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता भाई लाल बी. वैष्णव, उपाध्यक्ष छगनलाल मेवाड़ा, महासचिव सईदउद्दीन शेख, महासचिव कांतिभाई सोलंकी, महासचिव श्यामभाई तेनिया, महासचिव रवि कुमार सुरती, कार्यकारी अध्यक्ष हसमुखभाई पटेल, अधिवक्ता और उद्योगपति डी.सी. सोलंकी (अंकलेश्वर), अधिवक्ता बिपिनभाई राठौड़ (नवसारी), अधिवक्ता और नोटरी अश्विनभाई वैष्णव, अधिवक्ता महेंद्र सोलंकी और अन्य ने ज्योतिषी श्री राजू महाराज को सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी पुरस्कार प्राप्त करने पर बधाई और शुभकामनाएं दीं। राजू महाराज की सुविधानुसार सूरत में जल्द ही एक अभिनंदन समारोह आयोजित किया जाएगा।

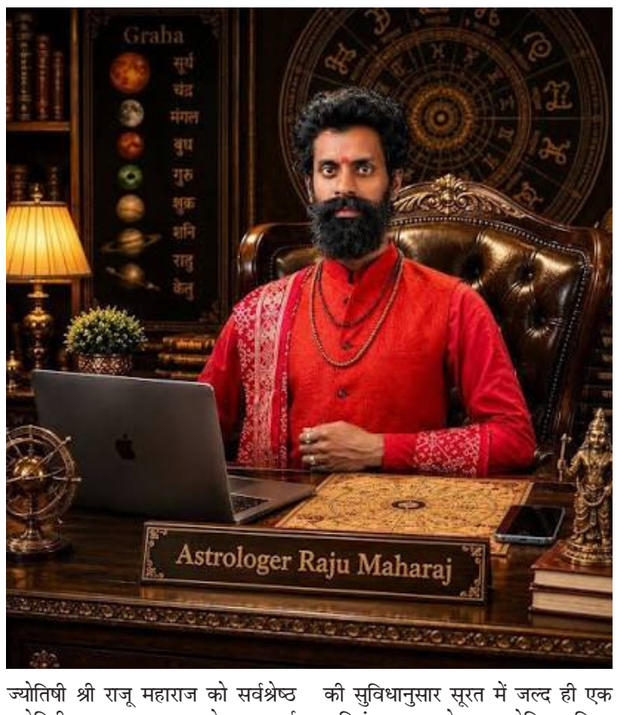

सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आधुनिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए आईआईटी-गांधीनगर में शीघ्र ही शुरू होगा 'समर्थ'

▸▸ गुजरात के इंजीनियरिंग विद्यार्थियों, प्रोफेसरों तथा औद्योगिक प्रोफेशनल्स के लिए अनुसंधान एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था

▸▸ आईआईटी-गांधीनगर करेगा गुजरात के कॉलेजों के साथ एमओयू, 5 वर्षों में 10 हजार विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने का आयोजन

गांधीनगर : भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विकास के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुसार मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य में सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विकास के लिए बहुत तेजी से कार्य हो रहा है। गुजरात को सेमीकंडक्टर क्षेत्र का हब बनाने के लिए, औद्योगिक निवेश के साथ इस क्षेत्र में कार्य करने के इच्छुक विद्यार्थियों, प्रोफेशनल्स तथा इंजीनियरिंग प्रोफेसर्स को आधुनिक प्रशिक्षण एवं अनुभव प्राप्त हो; इस दिशा में भी कार्य करना महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य को साकार करने के लिए शीघ्र ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)-गांधीनगर में सिलिकॉन एंड एडवांस्ड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग हब (समर्थ) शुरू होगा। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इस प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना होने जा रही है। इसके लिए, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गुजरात सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा आईआईटी-गांधीनगर द्वारा कुल 190 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। आईआईटी-गांधीनगर द्वारा इस केन्द्र के संचालन के लिए आवश्यक संसाधनों की खरीदारी तथा निर्माण कार्य के लिए कंसल्टेंट्स की नियुक्ति करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। शीघ्र ही यह केन्द्र प्रारंभ होगा और विद्यार्थी यहाँ आधुनिक तथा उद्योगों की मांग के अनुसार सेमीकंडक्टर क्षेत्र का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे।

'समर्थ' का उद्देश्य : इंजीनियरिंग विद्यार्थियों को बनाएगा फैब-रेडी

नवाचार, उद्योगों के साथ भागीदारी तथा व्यापक वर्कफोर्स के निर्माण द्वारा भारत में विश्व स्तरीय सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 'समर्थ' की स्थापना होने जा रही है। 'समर्थ' मुख्यतः सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए अनुसंधान, विकास और प्रशिक्षण प्रदान करने पर केन्द्रित रहेगा। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेजों के विद्यार्थी, प्रोफेसर्स और सेमीकंडक्टर उद्योगों में काम करने वाले विशेषज्ञ अपने कौशल को अपग्रेड करने के लिए आ सकेंगे। इस केन्द्र में इंजीनियरिंग विद्यार्थी फैब-रेडी बनेंगे अर्थात वे सेमीकंडक्टर प्लांट में कार्य करने के लिए तैयार होंगे। विद्यार्थियों में इस क्षेत्र के प्रति शुरू से ही जागरूकता आए; इसके लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे। स्थानीय एवं ग्लोबल भागीदारी द्वारा प्रशिक्षण, अनुसंधान और कौशल विकास के लिए 'समर्थ' एक समन्वित प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा।

गुजरात के कॉलेजों के साथ एमओयू किए जाएंगे

इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाने के लिए हाल में आईआईटी-गांधीनगर द्वारा गुजरात के अलग-अलग इंजीनियरिंग कॉलेजों के साथ एमओयू करने की तैयारियाँ चल रही हैं। इस केन्द्र में राज्य के विद्यार्थी मामूली शुल्क पर अध्ययन कर सकें; ऐसी व्यवस्था की गई है। यहाँ विशेष स्पेशलाइज्ड शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स भी चलाए जाएंगे तथा समर स्कूल द्वारा विद्यार्थियों को स्कूलों और कॉलेजों में इस क्षेत्र के विभिन्न पाठ्यक्रमों के बारे में पहले से ही अवगत कराया जाएगा।

5 वर्ष में 10 हजार विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने का आयोजन

'समर्थ' के माध्यम से क्षमता निर्माण के लिए आगामी पाँच वर्ष में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी की पढ़ाई कर रहे कुल 5600 विद्यार्थियों को इस केन्द्र के अंतर्गत लाया जाएगा। इसके अतिरिक्त; वॉकेशनल तथा टेक्निकल पाठ्यक्रमों में 1500 टेक्नीशियनों एवं सर्टिफिकेट कोर्स के अंतर्गत 1000 लोगों को प्रशिक्षण देने का आयोजन किया गया है। प्रोफेशनल व अपस्किलिंग में 230 फैकल्टी तथा इंडस्ट्री में कार्यरत 230 प्रोफेशनल्स को प्रशिक्षण मिल सकेगा। इसके अतिरिक्त; समर स्कूल तथा वन-डे एक्सपोज़र प्रोग्राम द्वारा 2700 से अधिक विद्यार्थियों को अवगत करने का आयोजन किया गया है। इस प्रकार; 10 हजार से अधिक वर्कफोर्स को आधुनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

'समर्थ' में कैसी सुविधाएँ विकसित की जाएँगी ?

यह केन्द्र आधुनिक सुविधाओं से सज्ज होगा। इसमें नैनो फैब्रिकेशन तथा सीएमओएस प्रक्रिया के प्रशिक्षण के लिए सुविधा का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त; डिवाइस प्रोसेस कैरेक्टराइजेशन सुविधा होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तथा चिप बनाने की प्रक्रिया की जाँच, टेस्टिंग और गुणवत्ता को चेक किया जा सकता है। साथ ही; सेमीकंडक्टर प्रोसेस एवं डिवाइस डिज़ाइन तथा डिवाइस मॉडलिंग लैब और आईसी डिज़ाइन एवं प्रोटोटाइप लैब का निर्माण किया जाएगा।

हमारा लक्ष्य केवल फैक्ट्री स्थापित करने तक सीमित नहीं है : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री ने स्पष्ट रूप से कहा है, "हमारा लक्ष्य केवल एक फैक्ट्री स्थापित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण इकोसिस्टम बनाना है। भारत अब सेमीकंडक्टर की पूरी वैल्यू चेन पर फोकस कर रहा है, जिसमें डिज़ाइन इंजीनियर से लेकर मशीन निर्माता और लॉजिस्टिक्स तक के सभी स्तर शामिल है। 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0' की घोषणा इसी दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। जैसे-जैसे उत्पादन बढ़ेगा, वैसे-वैसे भारत के भीतर ही सामग्री एवं कम्पोनेंट्स की मांग बढ़ेगी, जो स्थानीय उद्योगों के लिए सबसे बड़ा अवसर बनेगी।"

भावनगर परा रेलवे स्टेशन पर श्रमदान एवं सघन स्वच्छता अभियान आयोजित,संत निरंकारी मिशन के स्वयंसेवकों एवं रेलवे अधिकारियों-कर्मचारियों ने लिया बढ़-चढ़कर भाग

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल द्वारा स्वच्छ रेलवे–स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शुक्रवार, 03 जुलाई 2026 को मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा के मार्गदर्शन में भावनगर परा रेलवे स्टेशन पर संत निरंकारी मिशन, भावनगर के सहयोग से श्रमदान एवं सघन स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। अभियान में संत निरंकारी मिशन के स्वयंसेवी सदस्यों, रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के जवानों, टिकट निरीक्षकों, वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों तथा विभिन्न विभागों के शाखाधिकारियों एवं रेल कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर श्रमदान किया।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य रेलवे परिसरों में स्वच्छता के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना तथा यात्रियों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना है। अभियान के दौरान स्टेशन परिसर, रेल पटरी, प्लेटफार्म एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर व्यापक स्तर पर सफाई की गई। इस अवसर पर रेलवे की उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से यात्रियों से स्वच्छता अभियान में सहभागी बनने का आह्वान किया गया। यात्रियों से अपील की गई कि वे रेलवे परिसर, प्लेटफार्म तथा ट्रेनों में कचरा न फैलाकर स्वच्छता अभियान को सफल बनाने में सहयोग दें। साथ ही उन्हें स्वच्छता बनाए रखने, गंदगी न फैलाने तथा दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने का संदेश दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि स्वच्छ स्टेशन, स्वच्छ रेलवे और स्वच्छ भारत का लक्ष्य तभी साकार होगा जब प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन करेगा।

श्रमदान एवं स्वच्छता अभियान में अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री ऋत्विक शर्मा, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी, मंडल वाणिज्य प्रबंधक सुश्री नीलादेवी झाला, वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक श्री हरिश जनसारी, वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर श्री संतोष कुमार मिश्रा तथा मंडल सुरक्षा आयुक्त श्री अजय शर्मा सहित रेलवे के अनेक अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

भावनगर मंडल द्वारा समय-समय पर ऐसे जन-जागरूकता एवं स्वच्छता अभियान आयोजित किए जाते हैं, जिनका उद्देश्य यात्रियों में स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना तथा रेलवे परिसरों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं पर्यावरण अनुकूल बनाए रखना है।

अहमदाबाद मंडल में अत्याधुनिक स्टेट-ऑफ-द-आर्ट इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर का शुभारंभ

यात्रियों को सुरक्षित, समयबद्ध एवं विश्वसनीय रेल सेवाएं उपलब्ध कराने तथा रेल परिचालन को अत्याधुनिक तकनीक से सुदृढ़ बनाने की दिशा में पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अहमदाबाद मंडल में नवनिर्मित स्टेट-ऑफ-द-आर्ट इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर का आज मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश द्वारा विधिवत उद्घाटन किया गया। यह अत्याधुनिक नियंत्रण केंद्र अब पूर्ण रूप से कार्यशील हो गया है और उत्तर गुजरात क्षेत्र में रेल संचालन के "केंद्रीय तंत्र (Nerve Centre)" के रूप में कार्य करेगा।

लगभग 24,500 वर्ग फुट क्षेत्र में विकसित यह आधुनिक परिसर रेल परिचालन से जुड़े विभिन्न विभागों की नियंत्रण गतिविधियों को एक ही छत के नीचे एकीकृत करता है। इसके माध्यम से परिचालन दक्षता, समयपालन तथा यात्री सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार सुनिश्चित होगा। उद्घाटन के अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश ने कहा कि अहमदाबाद मंडल निरंतर आधुनिक तकनीकों को अपनाकर भारतीय रेल के डिजिटल परिवर्तन को गति दे रहा है। उन्होंने कहा कि यह इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर रेल संचालन को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी, उत्तरदायी एवं तकनीक-आधारित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस केंद्र के माध्यम से ट्रेनों के परिचालन की रियल-टाइम मॉनिटरिंग के साथ-साथ स्टेशनों एवं रेल परिसरों में भीड़ प्रबंधन (Crowd Management), स्वच्छता व्यवस्था, सुरक्षा एवं संरक्षा संबंधी गतिविधियों तथा किसी भी अप्रिय घटना (Untoward Incidents) पर चौबीसों घंटे प्रभावी निगरानी रखी जाएगी। विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय एवं त्वरित सूचना आदान-प्रदान से आपातकालीन परिस्थितियों में शीघ्र निर्णय एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित होगी।

अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाओं से सुसज्जित नियंत्रण केंद्र

इस स्टेट-ऑफ-द-आर्ट इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर में नवीनतम डिजिटल तकनीकों का समावेश किया गया है। लगभग 1,350 रूट किलोमीटर रेल नेटवर्क की रियल-टाइम हाई-रिज़ॉल्यूशन मॉनिटरिंग के लिए विशाल वीडियो डिस्प्ले यूनिट (VDU) वॉल स्थापित की गई है, जिससे किसी भी परिचालन स्थिति पर त्वरित निगरानी एवं निर्णय संभव हो सकेगा।

इस परिसर में फ्रेट एवं कोचिंग कंट्रोल, सिग्नल एवं दूरसंचार (S&T), इंजीनियरिंग, ट्रैक्शन तथा क्रू प्रबंधन सहित विभिन्न परिचालन इकाइयों को एकीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त रेलवे सुरक्षा बल (RPF) नियंत्रण कक्ष, आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ तथा कैरिज एवं वैगन (C&W) से संबंधित गतिविधियों का भी इसी परिसर से संचालन किया जाएगा। यात्रियों की सुविधा को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से इस केंद्र को रेल मदद (Rail Madad) शिकायत निवारण प्रणाली एवं नेशनल ट्रेन इन्क्वायरी सिस्टम (NTES) के साथ भी एकीकृत किया गया है, जिससे यात्रियों को ट्रेनों की अद्यतन एवं सटीक जानकारी समय पर उपलब्ध कराई जा सकेगी।

परिचालन दक्षता एवं समयपालन को मिलेगा नया आयाम

इस एकीकृत नियंत्रण केंद्र के माध्यम से प्रतिदिन संचालित होने वाली 130 से अधिक कोचिंग ट्रेनों तथा 160 से अधिक मालगाड़ियों के संचालन की सतत एवं समन्वित निगरानी की जाएगी। इससे समयपालन में और अधिक सटीकता आएगी तथा परिचालन संबंधी निर्णयों को त्वरित रूप से लागू किया जा सकेगा। साथ ही, लोको इंटरचेंज, जल आपूर्ति, पार्सल प्रबंधन, क्रू तैनाती तथा अन्य परिचालन प्रक्रियाओं में समन्वय एवं दक्षता बढ़ेगी। रियल-टाइम डेटा आधारित निगरानी प्रणाली के माध्यम से रेल सेवाएं अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी एवं विश्वसनीय बनेंगी।

आधुनिक कार्यस्थल के रूप में विकसित परिसर यह इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर केवल एक नियंत्रण भवन नहीं, बल्कि आधुनिक रेल प्रबंधन एवं तकनीकी समेकन का उत्कृष्ट उदाहरण है। 24×7 संचालित रहने वाले इस परिसर में कर्मचारियों के लिए अत्याधुनिक कार्यस्थल के साथ-साथ विश्राम कक्ष, मिनी बोर्ड रूम एवं समर्पित पार्किंग जैसी सुविधाएं भी विकसित की गई हैं, जिससे कार्य निष्पादन अधिक सुचारु, सुविधाजनक एवं प्रभावी हो सके।

बढ़ते रेल परिचालन एवं भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित यह इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर अहमदाबाद मंडल की परिचालन क्षमता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा पश्चिम रेलवे के डिजिटल एवं तकनीकी आधुनिकीकरण अभियान को और अधिक सशक्त बनाएगा।

सूरत नासिनगर विध्वंस घोटाले में कथित तौर पर संलिप्त छगनलाल मेवाड़ा ने अधिकारियों और व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। सूरत के नासीनगर में भूटिया परिवार के घर को गिराए जाने का मामला अब चर्चा का विषय बन चुका है, और गुजरात उच्च न्यायालय को अपमानित करने के सूरत नगर निगम के दुर्भावनापूर्ण इरादे का पर्दाफाश हो रहा है। सबसे अहम सवाल यह उठ रहा है कि यह तोड़फोड़ किसके आदेश पर की गई थी? आज तक एसएमसी अधिकारियों या पुलिस विभाग के किसी भी उच्च अधिकारी ने इस सवाल का कोई उचित और सटीक जवाब नहीं दिया है।

तो पहला सवाल यह उठता है कि सेना को युद्ध के लिए कहाँ भेजा जाए? क्या यह निर्णय सेनापति को लेना चाहिए या सेना को? क्या सेनापति के आदेश या अनुमति के बिना कोई भी सेना कभी भी शत्रु राज्य पर हमला नहीं कर सकती? फिर यहाँ, सूरत नगर निगम के नगर आयुक्त को इस बात की जानकारी नहीं है कि सूरत के वेदरोद नासिर नगर नामक क्षेत्र में 150 से अधिक मिट्टी की ईंटों से बने मकान ध्वस्त कर दिए गए हैं और निवासियों को बेघर कर दिया गया है? गुजरात उच्च न्यायालय में दायर हलफनामे में नगर आयुक्त ने कहा कि यह विध्वंस मेरी जानकारी के बिना किया गया था।

इसी तरह, शीर्ष पुलिस अधिकारी, यानी शहर के पुलिस आयुक्त, इस बात से अनभिज्ञ हैं कि एसओजी (विशेष अभियान समूह) के डीसीपी नाकुम, जो सीधे उनसे जुड़े हुए हैं और पुलिस आयुक्त के निर्देशों के बिना कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, स्वयं चुपचाप खड़े रहे और निवासियों को अपने घरों से बाहर आने का निर्देश देते रहे तथा विध्वंस करने वालों को संरक्षण प्रदान करते रहे। इस विध्वंस का मामला अब इतना पेचीदा हो गया है कि राज्य सरकार में बैठे भ्रष्ट नेताओं ने अपने प्रिय और उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों को बचाने की चाल के तहत, शहर के पुलिस आयुक्त को उच्च न्यायालय में पेशी की तारीखों से पहले ही अहमदाबाद स्थानांतरित कर दिया है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने डीसीपी नाकुम को अचानक आईपीएस अधिकारी बनाकर और इन गैर-जिम्मेदार अधिकारियों को पदोन्नति देकर स्थानांतरित करके गरीबों के गालों पर तमाचा मारकर "पाप" किया है।

सूरत नगर निगम के जिन पांच कर्मचारियों को इन बड़े मगरमच्छों को बचाने के लिए निलंबित किया गया है, वे भी लुटेरे का नाम आज तक साफ न करने और असली अपराधी को बेनकाब न करने के लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं। चंदाल बिल्डरों के समूह, टॉरेंट पावर, एसएमसी और पुलिस द्वारा किए गए इस फर्जी विध्वंस कार्य को देखते हुए, आज मानसून के मौसम में 150 परिवार बेघर हो गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सिर्फ कोरी बातें ही हुई हैं। कोई ठोस या स्पष्ट बात सामने नहीं आई है। मामला और भी पेचीदा इसलिए हो गया है क्योंकि इसे नगर पुलिस आयुक्त या नगरपालिका आयुक्त पेश कर रहे हैं। बारह दिनों तक कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हुआ, और अंत में बेतुके बचाव करके जनता की आंखों में धूल झोंकने का नाटक शुरू हो गया है।

एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जिस इलाके में तोड़फोड़ हुई है, वह किस जोन में आता है? राज्य सरकार अभी तक यह स्पष्ट नहीं कर पाई है कि यह उत्तरी जोन है या मध्य जोन। फिलहाल निलंबित कर्मचारी घर पर आराम करेंगे। और जांच सालों तक चलती रहेगी। इतना ही नहीं, यह मानना भी मुश्किल है कि सूरत नगर निगम के कुछ अधिकारियों ने अकेले ही यह सब किया है। इस पूरे घोटाले में सूरत नगर निगम आयुक्त से भी उच्च अधिकारी द्वारा जांच की जरूरत है, तभी असली दोषियों का पर्दाफाश होगा।

यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि निलंबित किए गए पांचों अधिकारियों ने एक महीने के दौरान कहा था कि वे वरिष्ठ अधिकारी का नाम उजागर करेंगे, लेकिन किसी अज्ञात कारण से उन्होंने नाम नहीं बताया। क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी भी घबराए हुए थे। इसी वजह से उनका निलंबन तीन बार रद्द किया गया, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारियों समेत सभी को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था।

क्योंकि आम तौर पर जब भी कोई तोड़फोड़ होती है, तो जिस पुलिस स्टेशन के अधिकारी की इमारत गिराई जानी होती है, उसका स्टाफ मौके पर मौजूद होता है। लेकिन इस बार खुद एसओजी के डीसीपी ने खड़े होकर तोड़फोड़ करवाई, जिससे साफ पता चलता है कि यह तोड़फोड़ बिल्डर लॉबी, टॉरेंट पावर और पुलिस के उच्च अधिकारियों व सूरत नगर निगम के बड़े अधिकारियों के इशारे पर की गई थी। इस तोड़फोड़ की एक और खासियत यह है कि अभी तक किसी भी बिल्डर या टॉरेंट पावर के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। इससे पता चलता है कि बड़े मगरमच्छों को बचाने के लिए निचले अधिकारियों को बलि का बकरा बनाने के खेल में पुलिस कमिश्नर का रातोंरात तबादला और बदनाम डीसीपी नाकुम को आईपीएस अधिकारी के पद पर पदोन्नति देना, ये सब कुछ शब्दों में बहुत कुछ बयां करते हैं। अब देखना यह है कि आने वाले समय में इस मामले में कौन बेनकाब होगा।

मंडल रेल प्रबंधक ने अमरेली में जनप्रतिनिधियों के साथ क्षेत्र की रेल परियोजनाओं, यात्री सुविधाओं और विकास कार्यों पर की विस्तृत चर्चा

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने 02 जुलाई, 2026 को अमरेली में गुजरात सरकार के माननीय कानून, न्याय, ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स, विधायी एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री कौशिकभाई कांतिभाई वेकरिया तथा अमरेली के माननीय सांसद श्री भरतभाई सुतरिया के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में अमरेली क्षेत्र में चल रही रेल परियोजनाओं की प्रगति, यात्री सुविधाओं के विस्तार, संरक्षा संबंधी कार्यों तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त विभिन्न मांगों एवं सुझावों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। मंडल रेल प्रबंधक ने जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए सभी विषयों पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए तथा

विभिन्न मामलों में रेलवे एवं स्थानीय प्रशासन के समन्वय से शीघ्र समाधान की आवश्यकता पर बल दिया।

बैठक के दौरान खीजड़िया–अमरेली गेज परिवर्तन परियोजना के अंतर्गत LC 21 को चौड़ा करने, LC 19 पर ROB एवं RUB का निर्माण करने, LC 02 स्थित अंडरब्रिज में जल निकासी की बेहतर व्यवस्था, LC 128 के स्थान पर प्रस्तावित रोड अंडर ब्रिज (RUB) का कार्य शीघ्र प्रारंभ करने, अमरेली यार्ड में ब्रॉडगेज लाइन संख्या 03 तथा प्रस्तावित मीटरगेज लाइन संख्या 1, 2 एवं 3 के कार्य को शीघ्र पूर्ण करने, वंदे भारत एक्सप्रेस का अमरेली जिले के चीतल स्टेशन पर ठहराव प्रदान करने तथा ब्रॉडगेज कार्य पूर्ण होने के पश्चात अमरेली को मुंबई, सूरत, अहमदाबाद एवं दिल्ली से जोड़ने वाली नई रेल सेवाएं प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा गया। अमरेली के उत्तर दिशा स्थित विद्यानगर कॉलोनी एवं आसपास के क्षेत्र तथा एल.सी. संख्या 18 एवं 19 के मध्य जल भराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए मंडल रेल प्रबंधक द्वारा स्थानीय प्रशासन को जल निकास के लिए एक समावेशी कार्य योजना बनाने का परामर्श दिया गया एवं रेल प्रशासन द्वारा पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया गया।

रेलवे प्रशासन ने बताया कि रेलवे परिसर में स्थित हनुमान मंदिर, शिव मंदिर एवं मामादेव मंदिर के पुनर्स्थापन के उपरांत कार्य में तेजी लाई जा सकेगी तथा इस संबंध में सहयोग का अनुरोध किया गया। मंडल रेल प्रबंधक ने जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए सभी विषयों पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने कहा कि पश्चिम रेलवे यात्रियों की सुविधा, संरक्षा तथा क्षेत्रीय विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जनप्रतिनिधियों के साथ निरंतर समन्वय स्थापित कर कार्य कर रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रेलवे एवं स्थानीय प्रशासन के सहयोग से विभिन्न विकास परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से आगे बढ़ाया जाएगा।

बैठक में भावनगर मंडल के विभिन्न विभागों के शाखा अधिकारी एवं संबंधित कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

नई दिल्ली में 3 जुलाई, 2026 को हुई बॉट बैठक के लिए फियो की सिफारिशें

1. निर्यात वृद्धि को बनाए रखने के लिए प्राथमिक क्षेत्र निर्यात ऋण को सुदृढ़ करना

वैश्विक व्यापारिक माहौल में अनिश्चितता के बावजूद भारतीय निर्यात सुदृढ़ रहा है। हालांकि, इस वृद्धि को संस्थागत ऋण का पर्याप्त समर्थन नहीं मिल रहा है।

निर्यात ऋण के लिए प्राथमिक क्षेत्र कर्ज (पीएसएल) में काफी गिरावट आई है, हाल की अवधि में इसमें लगभग 14% की कमी आई है। इससे नकदी की गंभीर समस्याएं पैदा हुई हैं, खासकर एमएसएमई निर्यातकों के लिए, जो भारत के निर्यात क्षेत्र की रीढ़ हैं।

ऐसे समय में, जब निर्यातक लंबे भुगतान चक्र, उच्च लॉजिस्टिक्स लागत, बढ़ी हुई अनुपालन आवश्यकताओं और तेज वैश्विक प्रतिस्पर्धा से जूझ रहे हैं, सस्ती कार्यशील पूंजी तक समय पर पहुंच पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। शिपमेंट से पहले और शिपमेंट के बाद ऋण की अपर्याप्त उपलब्धता, सीधे तौर पर उनके निर्यात ऑर्डर को पूरा करने, नए बाजारों में विस्तार करने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने रहने की क्षमता को प्रभावित करती है।

इसलिए, हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह भारतीय रिज़र्व बैंक और बैंकिंग क्षेत्र के साथ मिलकर निर्यात ऋण को एक रणनीतिक प्राथमिकता के रूप में बहाल करे, अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर निर्यात वित्तीय सहायता की पर्याप्त और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करे और बैंकों को निर्यातकों के प्रति ज़्यादा आसान तरीका अपनाने के लिए प्रोत्साहित करे। एक सक्रिय और उत्तरदायी निर्यात ऋण प्रणाली भारत के 2 ट्रिलियन डॉलर निर्यात अर्थव्यवस्था बनने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए अनिवार्य है।

2. भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने वाली लॉजिस्टिक्स चुनौतियों का समाधान

भारत की निर्यात वृद्धि भरोसेमंद, कुशल और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी लॉजिस्टिक्स सेवाओं पर अधिक निर्भर करेगी। लेकिन, निर्यातकों को अभी भी कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि उच्च समुद्री ढुलाई दरें, कंटेनरों और जहाज के लिए जगह की अपर्याप्त उपलब्धता और शिपिंग लाइनों और उनके एजेंटों द्वारा लगाए जाने वाले कई गैर-पारदर्शी और मनमाने शुल्क। इसके साथ ही निर्यातकों को भीड़भाड़, पीक सीज़न, दस्तावेज़ीकरण हिरासत और बिलंब शुल्क जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। ये सभी कारक लॉजिस्टिक्स लागत को काफी बढ़ा रहे हैं, भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धा को कम कर रहे हैं और निर्यातकों, खासकर एमएसएमई, की वैश्विक बाजारों में डिलीवरी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की क्षमता को प्रभावित कर रहे हैं।

हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह इस मुद्दे को उच्च प्राथमिकता दे और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, पोत परिवहन महानिदेशालय और अन्य संबंधित पक्षों के साथ मिलकर ऐसा ढाँचा तैयार करे जो माल भाड़े से जुड़ी लागतों में अधिक पारदर्शिता और उचित शुल्क सुनिश्चित करे, भारतीय निर्यात माल के लिए कंटेनर और जहाजों की उपलब्धता में सुधार करे और निर्यातकों तथा शिपिंग लाइनों के बीच नियमित संवाद को आसान बनाए। माल भाड़ा और लॉजिस्टिक्स से जुड़े मुद्दों की लगातार निगरानी के लिए एक संस्थागत व्यवस्था पर भी विचार किया जा सकता है, ताकि बाजार के उथल-पुथल के दौरान त्वरित हस्तक्षेप संभव हो सके। इन चुनौतियों के समाधान से लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी, भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा बेहतर होगी और देश के महत्वाकांक्षी निर्यात विकास लक्ष्यों को समर्थन मिलेगा।

3. वैश्विक हरित बदलाव के लिए भारतीय निर्यातकों का समर्थन

वैश्विक व्यापार संरचनात्मक रूप से बदल रहा है, क्योंकि बाजार में पहुँच पाने के लिए सतत विकास की भावना अब एक अनिवार्य शर्त बनती जा रही है। प्रमुख व्यापारिक साझेदार, खासकर यूरोपीय संघ, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम) के माध्यम से, पर्यावरण से जुड़ी सख्त अनुपालन आवश्यकताएँ लागू कर रहे हैं, जो इस्पात, एल्युमिनियम, सीमेंट और बहुत जल्द रसायन, वस्त्र और इंजीनियरिंग उत्पाद जैसे क्षेत्रों को गंभीर रूप से प्रभावित करेंगी। भारतीय निर्यातकों, विशेषकर एमएसएमई, के लिए चुनौती केवल अनुपालन तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके लिए उत्पादन प्रक्रियाओं और आपूर्ति श्रृंखलाओं में कार्बन उत्सर्जन को मापने, रिपोर्ट करने और घटाने से जुड़ा बड़ा वित्तीय बोझ भी है। पर्याप्त संस्थागत समर्थन के बिना, कई निर्यातक प्रीमियम वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा खोने का जोखिम उठाते हैं और उन्हें ऐसे कार्बन-संबंधित सीमाशुल्क का भुगतान करना पड़ सकता है, जो भारत के पारंपरिक लागत लाभ को कम कर देगा। इसलिए हम सरकार से एक शीर्ष हरित बदलाव कोष स्थापित करने का अनुरोध करते हैं, जो निर्यातकों को स्वच्छ तकनीकों को अपनाने, ऊर्जा दक्षता में सुधार करने और कार्बन तीव्रता कम करने में मदद करने के लिए समर्पित हो। इसके साथ ही क्षेत्र-विशेष हरित बदलाव हेल्पडेस्क भी होना चाहिए, जो कार्बन को मापने, सतत विकास की रिपोर्टिंग करने, पर्यावरण प्रमाणीकरण और उभरते अंतरराष्ट्रीय नियमों के पालन पर तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करें। वित्तीय सहायता, रियायती वित्त और प्रतिस्पर्धात्मक तकनीकी हस्तांतरण, साथ ही कार्बन ऑडिट और मूल-स्थान जांच प्रणाली के लिए समर्थन, भारतीय निर्यातकों को बदलते हुए वैश्विक व्यापार ढांचे में सफलतापूर्वक आगे बढ़ने में सक्षम बनाएंगे। आज हरित बदलाव में निवेश करना न केवल मौजूदा निर्यात बाजारों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है, बल्कि भारत को तेज़ी से सतत विकास के प्रति जागरूक वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के बीच एक पसंदीदा स्रोत गंतव्य देश के रूप में स्थापित करने के लिए भी ज़रूरी है।

4. पर्यटन और खुदरा निर्यात को बढ़ावा देने के क्रम में विदेशी पर्यटकों के लिए जीएसटी रिफंड लागू करना

एकीकृत वस्तु और सेवा कर (आईजीएसटी) अधिनियम, 2017 की धारा 15 भारत में सामान खरीदने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए जीएसटी रिफंड की सुविधा प्रदान करती है। लेकिन, जीएसटी लागू होने के लगभग नौ साल बीत जाने के बावजूद, यह महत्वपूर्ण प्रावधान अभी तक लागू नहीं हुआ है। दुनिया भर में, वीएटी/जीएसटी रिफंड योजनाएँ पर्यटन बढ़ावा देने की रणनीतियों का एक अहम हिस्सा बन गई हैं और इन योजनाओं ने अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को स्थानीय उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करके खुदरा निर्यात को काफी बढ़ावा दिया है।